ten our prestige before the country? Would the Huose and the Parliamentary Affairs Minister consider whether this practice should be followed?

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE STRIKE BY UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS ALL OVER THE COUNTRY

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य ...) मान्यवर, आज देश भर के विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापक, जिनकी संख्या शायद 2 लाख 30 हजार है, वह अपनी हड़ताल के पन्द्रहवें दिन पर पहुंचे हैं। यह हड़ताल 4 अगस्त से हुई थी। जहां तक मुझे स्मरण है, हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों के इतिहास में ऐसी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पहले कभी नहीं हुई। मानव संसाधन मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव यहां पर उपस्थित हैं और उनके कार्यकाल में ऐसी हड़ताल हो, इसका मुझे दुख होता है। उनसे यह अपेक्षा थी कि वे इस स्थिति तक अध्यापकों को पहुंचने ही नहीं देंगे। उन्होंने जिस समय टोकन-स्ट्राइक की थी एक दिन की, तभी अपेक्षा की गयी थी कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा और यह टोकन, जो उन्होंने एक प्रकार का संकेत दिया है, उस संकेत को समझकर भारत सरकार समुचित कार्यवाही करेगी और उनकी बातें सुन कर कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ नहीं दूसरे सदन में जो चर्चा है तथा उसमें मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि उससे मुझे लगता है कि स्थिति और जटिल हुई है सुलझने के बजाय। उनको शायद ऐसा दिखायी देने लगा है कि अध्यापकों में वह क्लाउट नहीं है जो बाकी विभिन्न वर्गों में है और इसीलिए उनकी बात न्यायोचित होते हुए भी सुनी नहीं जाती। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करता हूं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी कई ऐसे वर्ग हैं जो अगर हड़ताल करते हैं तो उस हड़ताल का सीधा प्रभाव साधारण जीवन पर पड़ता है और इस ढंग से पड़ता है कि जिसके कारण सरकार को सही या गलत कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन हड़ताल का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता दूरगामी प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है और यह राष्ट्र के लिए बहुत घातक, बहुत हानिकारक है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज से 4 साल पहले दिल्ली में ही मुझे स्मरण है कि 109 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। उससे भी देश को हानि हुई। लेकिन वह दिखायी नहीं देती। इसीलिए मैंने इस शब्द का उपयोग किया कि शायद अध्यापकों के पास क्लाउट नहीं है जो कुछ और वर्गों के पास है और जैसे ही हड़ताल होती है सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करती है, कुछ न कुछ तरीका निकालती है, रास्ता निकालती है समझौता कर लेती है और ठीक कर लेती है।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Has it happened in the case of sick textile mills? Has it happened in the case of textile workers?

SHRI LAL K. ADVANI: I have not mentioned any particular example; I have merely stated.

उपसभाध्यक्ष महोदय, कम से कम नरसिंहराव जी से मैं यह अपेक्षा करता था कि वे इस चीज का केवल टैक्निकलटीज के आधार पर नहीं देखेंगे कि हड़ताल पर है, क्या बात करें। उस दिन जब प्रश्नोत्तर हो रहे थे और मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि यह कैसी बात कह दी। सरकार ने 17 जून को एक घोषणा की मेहरोत्रा कमेटी के आधार पर और उस घोषणा के कारण ही यह उसके बाद की घटनाएं हुई। मैं उस घोषणा का विरोध करता हूं, मूलतः विरोध करता हूं कि गलत है। उसमें कई ऐसे पहलू हैं, मैं समझता हूं, कि जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल होगा। मैं मानता हूं कि उस घोषणा में भारत सरकार ने 1973 में जो पैरिटी का सिद्धांत स्वीकार किया था अध्यापकों और क्लास-I के बीच, उस पैरिटी के सिद्धांत का हनन किया है। मैं यह मानता हूं कि उस घोषणा में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला किया गया है

और मैं यह भी मानता हूं कि इस घोषणा को अगर पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा तो एक प्रकार से हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का ब्युरोक्रटायजेशन हो जाएगा । मैं इन तीन कारणों से इस घोषणा को उचित नहीं मानता हूं और मैं समझता हूं कि उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो 17 जून को घोषणा हुई और हिन्दुस्तान के 2 लाख से अधिक अध्यापकों को नए वेतनमान मिले । साधारणतः तो इसके कारण हर्ष होना चाहिए था, स्वागत होना चाहिए था विशेषकर इसलिए कि 14 साल के बाद कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को बढ़े हुये वेतन मिले थे ।

1973 की जनवरी में जो वेतनमान में वृद्धि हुई सेन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, उसी सेन कमेटी ने कहा था कि हर पांच साल में वेतनमान का पुनरीक्षण होना चाहिये, रिवीजन होना चाहिये । 1973 के बाद 1978 में रिवीजन होना चाहिये था, 1978 में रिवीजन नहीं हुआ । उसके बाद 1983 में होना चाहिये था, 1983 में नहीं हुआ और अब आकर 1987 में रिवीजन हुआ तो उसके कारण खुशी होनी चाहिये थी, खुशी के बजाय ऐसी नाराजगी हुई है कि हिन्दुस्तान भर में जो पहले कभी नहीं हुआ वह हो रहा है और सारे हिन्दुस्तान के अध्यापकों ने हड़ताल कर दी ।

इतना ही नहीं, यहां पर ट्रेड यूनियन की बात भी कही गई, लेकिन हिन्दुस्तान के 6 विश्वविद्यालयों में जिनमें विश्व भारती भी शामिल है, जिसमें जे० एन० यू० भी शामिल है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल है, इन विश्वविद्यालयों ने इस घोषणा को अस्वीकार किया है और कहा है कि हम इससे सहमत नहीं है और इनकी कोई अध्यापकों की ट्रेड यूनियन है, अध्यापकों की ऐसोशियेशन है तो वह अपनी हैसियत से कर सकते हैं, यह आरोप भी नहीं लगा सकते हैं । लेकिन वे मानते हैं कि यह घोषणा हमारी स्वायत्तता पर अतिक्रमण है, हमारी स्वायत्तता पर आघात है और इसीलिये हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मेरी अध्यापकों से जो बात हुई है उससे मुझे इस बात का भी अफसोस हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से जितना इनफ्लेशन का न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिये था 14 साल बाद, वह इन प्रस्तावों द्वारा नहीं होता है और कुछ लेवल्स पर कुछ स्केल्स में तो 36 परसेंट का इनफ्लेशन अन-कवर्ड रह जाता है, कहीं कहीं पूरा भी हो जाता है । लेकिन उनकी शिकायत आर्थिक कम है, प्रायः नगण्य है, प्रमुख रूप से उनकी शिकायत जो है, इस योजना के कारण जो उनका स्टेटस है, उस पर प्रभाव पड़ता है । सामाजिक जीवन में जो अध्यापक की स्थिति है और कालेजों और विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार के अध्यापक आकृष्ट होकर आने चाहिये, उस पर प्रभाव पड़ने के कारण वहां पर गंभीर चिन्ता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हर एक कमेटी कहती आई है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिसके कारण योग्यतम लोग अध्यापन कार्य में लगें । मैं अगर गलती नहीं करता हूं तो मेहरोत्रा कमेटी में, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही ये प्रस्ताव लाये गये हैं, उसकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो छात्र विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण होते हैं, उनके सामने जो विकल्प होते हैं, जो रास्ते हैं उनमें से अध्यापन कार्य पांचवीं चायस है । मैं देख रहा था "चेलेंज आफ ऐजुकेशन आन पालिसी पर्सपक्टिव" जो शिक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष जारी किया था, उसमें भी इसका जिक्र है चाहे वह आइडेंटिफाई नहीं किया है कि पांचवीं चायस है । लेकिन इसमें भी कहा गया है :

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

"Teaching has come the last choice in the job market." अब अपेक्षा यह है कि यह जो नई ऐजुकेशन पालिसी हमने बनाई है और जिसका आश्रय लेकर बार बार मंत्री जी अपने प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो उस नई शिक्षा नीति में, स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश की जायेगी? व्यवस्था ऐसी हो रही है जिसके कारण और खराब स्थिति होगी। मैंने जैसे पहले कहा, मैं इसको ब्यूरोक्रेटाइजेशन मानता हूं। ब्यूरोक्रेसी और शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी सब जगह दुनियां भर में और हिन्दुस्तान में भी प्रयत्न यह होता है कि ग्रेडस और स्केल कम से कम हों। फर्स्ट पे कमीशन बना था, बहुत सारे ग्रेडस थे, उनको कम किया। सेकिंड पे कमीशन बना तो देखा कि जितने ग्रेड कम किये थे, फिर से उतने बढ़ गए और फिर कम करते गये। फोर्थ पे-कमीशन अभी-अभी बना था और जब उस कमीशन ने अपना काम शुरू किया तो उसके सामने बहुत से पे-स्केल्स थे उन स्केलों को कम करके उन्होंने 36 कर दिये। इसके लिये उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया जो बहुत उपयुक्त है उन्होंने कहा

"A few grades with clearly defined differences of responsibilities corresponding to different scales of pay will be acceptable, but posts graded and paid differently, yet without discernible differentiation of duties can have an adverse effect on morale."

यह तर्क इतना सीधा है, साफ है कि किसी के भी समझ में आ सकता है। इसलिये इस 17 जून की घोषणा से देश के अध्यापक भौचक्के रह गये, अचम्भे में आ गये। मेहरोत्रा कमेटी की सिफारिश में पहले के जो तीन ग्रेड थे—लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर इनके स्थान पर 6 ग्रेड लाने की कोशिश की गयी है। मंत्रालय ने 7 ग्रेड कर दिये हैं। इसका क्या तर्क है? मैं मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा लेकिन मे समझ में नहीं आया। मुझे लगताहै कि ग्रेडस की मल्टीप्लिसिटी के कारण कन्फ्यूजन पैदा होता है, परस्पर अन्तर-विरोध होता है, इन्टरनल कांफलिक्ट पैदा होते हैं। लेकिन एक प्रकार से ऊपर बैठे हुये ब्यूरोक्रेसी डिवाइड एंड रूल की पालिम चलाना चाहते हैं क्योंकि उस को अपनाने में सुविधा होती है। इसीलिये सबसे प्रमुख आपत्ति देश के अध्यापकों की यह है कि जो पूर्व व्यवस्था थी उसको बदला जा रहा है। उसको बदलने के करण उसका एक और भंयकर परिणाम निकलता है। बड़े घर्ष के बाद 1983 में जो उन को मेरिट प्रोमोशन मिली थी वह साथ साथ खत्म हो जाती है। इससे पहले पूरा प्रोमोशन हो सकता था। लेक्चरार से प्रोमोशन पाकर रीडर बनता था और रीडर से प्रोमोशन पाकर प्रोफेसर बनता था। लेकिन नयी व्यवस्था में लेक्चरार जो भर्ती होगा आजीवन लेक्चरार ही रहेगा। प्रोमोशन के माध्यम से उस को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं होगा। साधारणतया वह कम्पीटीशन में जायेगा उसके द्वारा ही रीडर बन सकता है उसके द्वारा ही प्रोफेसर बना सकता है। 1983 में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के टीचर्स ने प्राप्त की थी। सेन कमेटी की सिफारिशों के कारण, संघर्ष के कारण और सबसे बढ़कर हाई कोर्ट के इन्टरवेंशन के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस समय हस्तक्षेप किया था और हस्तक्षेप के कारण यह किया गया था कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम एक बार टीचर को, लेक्चरार को प्रोमोशन मिल सके अपनी सेवा के आधार पर और चयन के आधार पर। मैंने देखा कि मंत्री ने यह धारणा पैदा करने की कोशिश की कि लेक्चरार ईवेल्युशन के खिलाफ हैं। वह चाहते हैं कि अटोमेटिकली विद द अफलेक्स आफ टाइम उनको रीडरशिप मिल जाये, विद अफलेक्स आफ टाइम उनको प्रोफेसरशिप मिल जाये। मैं समझता हूं यह कहना उनके साथ भारी अन्याय करना है क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में जो यह कहा कि आप उनके लिए ईवेल्युशन का कोई प्रोसैस कोई मापदण्ड तय कीजिए हर एक युनिवर्सिटी में। दिल्ली विश्वविद्यालय में उसके मापदण्ड

तय हुए हैं। सेलेक्शन कमेटी बैठती है। मैं जानता हूं कि आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक तो दिल्ली में हूं और यहां उनसे मिलते रहते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण दे कर मंत्री जी ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि यह मैरिट प्रोमोशन स्कीम जो है वह विफल हुई है। मंत्री जी के अनुसार इस मेरिट प्रोमोशन स्कीम से रीडर्स और प्रोफैसर्स का सिर नीचे गिरा है। मैं कई लेक्चरर्स को जानता हूं जिनको इस प्रकार के वाक्यों से जो मंत्री जी ने दिये हैं या यू० जी० सी० के चेयरमैन ने दिये हैं, उनको उससे बहुत आघात हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सवीपिंग स्टेटमेंट बहुत अन्यायपूर्ण है। महरोत्रा कमेटी ने कहा --

Owing to its mal-implementation, the scheme appears to have failed by and large to achieve its primary objective of rewarding merit. It has virtually culminated in time-bound promotions and the pursuit of excellence has fallen by the wayside.

यह मैं उनका वाक्य उदधृत करता हूं। मंत्री जी ने उस सदन में जो बयान दिया है उसको मैं कोट कर रहा हूं --

In the Delhi University for example, after the implementation of the merit promotion scheme, professors account for 35 per cent of the total teachers, readers 45 per cent and lecturers a mere 20 per cent

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : थोड़ा आप ब्रीफ में बोलिये। बोलने वाले स्पीकर्स बहुत हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष जी मंत्री जी का कहना है कि इस मेरिट प्रोमोशन स्कीम का परिणाम यह हुआ है कि वहां पर, दिल्ली युनिवर्सिटी में लेक्चरर्स केवल 20 परसेन्ट हैं। इस फीगर को देखने पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने इस संबंध में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला कि यह जो 20 परसेंन्ट उन्होंने गिना है समें खाली युनिवर्सिटी के लेक्चरर गिने हैं। दिल्ली में जो कालेजेज हैं उनके लेक्चरर्स को नहीं गिना है। कुल मिलाकर दिल्ली में 5776 लेक्चरर्स हैं। 5776 इन लेक्चरर्स में से 144 रीडर हुए है और 124 रीडर्स प्रोफेसर्स हुए। यह प्रोफेसर्स और रीडर्स का परसेन्ट इतना कम हो जाएगा कि यह तर्क कहीं खड़ा नहीं रह सकता है। यद्यपि यह जो तर्क है इसको और फीगर्स को मैं इस मामले में रिलेवेन्ट नहीं मानता।

That may be all right for a bureaucratic structure.

मंत्री जी ने इसे इन्वार्टिड पिरामिड कहा है यह जो पिरामिड वाली थीसिस है इसमें ब्यूरोक्रेटिक हाइरारकी नजर आती है।

एजूकेशनल इंस्टिटयूशन्स में एकान्टेबिलिटी आप रीडर्स और प्रोफेसर्स का जहां तक संबंध है -

It is to the institution as a whole and not to a particular individual who is at the top of the hierarchy. It is to the students whom he is teaching.

यह जो कल्पना है, इसके कारण यह जो इंवर्टिड पिरामिड की थीसिस है, इसको में बेसिक्ली अनुपयुक्त मानता हूं, इसको इरिलेवन्ट और इनएप्लीकेवल मानता हूं। यह बात सच नहीं है और इसमें सचाई नहीं हैं। आंकड़ों के हिसाब से भी यह इंवर्टेड पिरिमिड नहीं बनता है। जो 7576 लेक्चरर्स हैं, विभिन्न कालेजों और दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनमें से 144 रीडर बने हैं और 124 प्रोफेसर्स बने हैं। आंकड़ों के हिसाब से यह सही नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): मैं यह जाना चाहता हूं कि सीनियर लेक्चरर्स कितने बने हैं?

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Ask the Minister, he will tell you.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I have information from the Government. They do propose an inverse pyramid. They say the supplementary staff should be less and scientific and technical staff should be more.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने यह भी जानकारी की है कि क्या केवल एफक्स आफ टाइम से कोई रीडर बन जाता है, कोई प्रोफैसर बन जाता है, क्या यह सही है ? ऐसे उदाहरण है कि सयम आ गया है जिसके आधार पर उनको रीडर बनना चाहिए । लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उनको उपयुक्त नहीं पाया और मैंने पाया कि सभी डिपार्टमेंट में और सब विभागों में ऐसे लोग है जो सयम बीत जाने के बाद भी

They are not able to come up to the standards, the Selection Committee has laid for them. They are not promoted to Readership. They are not promoted to Professorship.

अर्थात, यह कहना कि दिल्ली के और हिन्दुस्तान के अध्यापकों का संघर्ष इस आधार पर है कि उनका ऐवेल्यूए-शन न हो, यह बात सही नहीं है । हिन्दुस्तान के संदर्भ में मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि क्लास वन सर्विसेज में आटो-मैटिक अपवर्ड मोबेलिटी हो और अध्यापकों को ही खाली इसके लिये अलग रखा जाय उनके यहां पर आटोमैटिक मौबेलिटी नहीं होगी । फिर भी क्योंकि हिन्दुस्तान में उन्हीं अध्यापकों ने इस बात को स्वीकार किया और जब हाई कोर्ट ने माना कि एवेल्यूशन होना चाहिए और सलेक्शन कमेटी बननी चाहिए जिसमें रिप्रेजन्टेटिव कौन कौन हैं, विजिटर के भी रिप्रेजेन्टेटिव रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है, यह कोई तर्क है जिसके आधा पर उनकी बात न मानी जाय ।

उपसभाध्यक्ष जी, ग्रेड व प्रमोशन उसके बाद तीसरा मुद्दा है सेन्टर 80% ग्रांट देगी और स्टेटस 20 परसेन्ट देगी। यह तीसरा एक विषय है कि पर झगड़ा हो रहा है । मैंने किसी से पूछा कि उसका फाइनेंशियल एम्पलीकेशन कितना होगा । आज अगर सेन्टर फैसला कर दे कि क्योंकि हम नयी एजूकशन पालिसी लाये हैं और *उस नयी एजुकेशन पालिसी में हम समझते* हैं कि पिसट जो है वह टीचर्स हैं, और हम इस न्यू पे स्केल्स में प्रपोज करते हैं कि नये पे स्केल होने चाहिए उसके कारण जितना भी बर्डन स्टेटस पर पडेगा हम भुगतेंगे । सेन्ट परसेन्ट देंगे तो इसमें कितना एडीशनल एक्सपें-डिचर होगा जिस पर यह सारा झगड़ा हो रहा है तो मुझे बताया गया कि 33क रोड़ रुपया ।

Rs. 33 crores is the additional financial entailment. If the Government were to accept 100 per cent responsibility for these pay scales and if Rs. 33 crores is the financial liability that it entails,

मेरी समझ में नहीं आता कि इसको इश्यू बनाया क्यों गया । यह कहना कि सेन्टर एडवायजरी बोर्ड में यह बात मान ली गई थी यह शायद तथ्यों के हिसाब से भी सही नहीं है । शायद 6 मंत्री ऐसे थे विभिन्न राज्यों के जिन्होंने कहा कि सेन्ट परसेन्ट हमको मिलना चाहिए, सेन्टर की ओर से जो 20 परसेन्ट का बोझ हम डाल रहे हो यह ठीक नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष जी, आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा और वह यह है कि इस पूरे संदर्भ में अध्यापकों से जो चर्चा होनी चाहिए जो कन्सलटेशन होना चाहिए था वह कन्सल-टेशन नहीं हुआ ।...(व्यवधान)... कन्सलटेशन का इनका अपना एक तरीका है वह यह है कि पिछले साल महरोत्रा कमेटी ने जब रिपोर्ट दे दी यू० जी० सी० को तो यू० जी० सी० ने अध्यापकों के प्रतिनिधियों को बुलाया सलाह के लिये, 11 अगस्त, 1986 को और जब वे सलाह करने के लिये गये, कन्सलटेशन के लिये गये तो यू० जी० सी० के चैयरमैन ने उनको कहा कि हमने मैहरोत्रा कमेटी की रिपोर्ट को इन्डोर्स करके मंत्रालय के पास भेज दिया है । यह जानकारी देने के लिये हमने आपको बुलाया था । इसके बाद मंत्री जी से मैं अपेक्षा करता था कि मंत्री जी इस पर फाइनल फैसला करें इससे पहले कम से कम विस्तार से अध्यापकों से चर्चा कर लेते । वह भी चर्चा हुई बताया । यह कब हुई थी ? 10-11 और 12 जून को, अभी इसी साल के 10, 11 और 12 जून को मंत्री जी, की चर्चा हुई थी अध्यापकों के प्रतिनिधियों से और उस चर्चा में उनको जानकारी यह दी गई कि कैबिनेट में एक और दो मई को मैहरोत्रा कमेंटी की रेकमडेंशस को स्वीकार किया गया है और उसके आधार पर हमने फैसला कर लिया है और इसलिये जो सेन्ट्रल इश्यू हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन पर

चर्चा नहीं हो सकती। अब पैरीफल पर कौन सी चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम हुआ यह तो शायद मंत्री जी स्वयं बता सकेंगे। लेकिन में इन दोनों उदाहरणों को देकर आज फिर से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सरकार इसको प्रेस्टिज इश्यू न बनायें, प्रतिष्ठा और सम्मान का इश्यू न बनाये, मंत्रालय के अधिकारियों को बात करने के लिये न कहे बल्कि वे स्वयं प्रतिनिधियों को बुलाकर बात

4.00 P.M. करें। स्ट्राक चलती है या नहीं चलती है उससे कोई संबंध नहीं है। आप हड़ताल वापिस लीजिये तो बात होगी, यह कोई मिल मालिक करे तो उसके लिये ठीक होगा लेकिन हिन्दुस्तान के मानव संसाधन मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव को यह बात शोभा नहीं देती कि वह कहें कि स्ट्राइक विदड्रा करो तो बात करेंगे। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर यह मामला उलझता गया तो कितने दिनों तक छात्रों का विद्यार्थियों का नुकसान होगा यह मैं नहीं कह सकता। इसीलिये सब से पहले इस बात की जरूरत है कि आप उनके प्रतिनिधियों को बुला लें। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि इस सदन में कुछ हमारे साथी हैं, सम्मानित सदस्य हैं, जो अध्यापक हैं यूनीवर्सिटीज में कालेज में पढ़ाते हैं, उस सदन में भी हैं, ऐसे सभी अध्यापकों को बुला कर के उन से सलाह कर लीजिये, राय ले लीजिये और उनके बाकी के प्रतिनिधियों को भी बुला लीजिये। प्रमुख रूप से जब ऐसी स्थिति आ गई है कि यह अध्यापक पे स्केल्ज के मोनिटरी कंटेंट के बारे में झगड़ा नहीं करते हैं लेकिन अपने स्थान के लिये स्टेटस के लिये और उसके लिये कालेजेज और यूनीवर्सिटीज में देश के अच्छे से अच्छे गुणी योग्य लोग आते रहें इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये और पे स्केल्ज ऐसे होने चाहियें यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस में कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिये। एक बात और पे स्केल्ज के साथ-साथ सर्विस कंडीशन उपयुक्त नहीं है। यह कहना जरूरी कि 17 तारीख के बयान में कहा गया है कि जो-जो यूनीवर्सिटीज हमारी शर्तों को मानेंगी, सर्विस कंडीशन को मानेंगी वे ही पे स्केल्ज बढ़ायें, यह बहुत बड़ी गलती है और एक बहुत बड़ा अतिक्रमण है यूनीवर्सिटीज की स्वायतता में दखल देने का। मैं उन 6 यूनीवर्सिटीज को बधाई देता हूं जिन्होंने चाहे हल्के तौर से नरम तरीके से ही सही, विश्वभारती ने तो बहुत जोरदार रेजोल्यूशन पास किया है लेकिन बाकी ने भी जिस प्रकार से अपनी स्वायतता पर केन्द्रीय सरकार के इस आक्रमण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते। मैं उनको बधाई देता हूं उनका अभिनन्दन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में जल्दी से जल्दी योग्य कदम उठायेंगे। धन्यवाद।

डा० (श्रीमती) नाजमा हपतुल्ला (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे कि आज आडवाणी जी ने कहा कि आज हम इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं वह अन्दाज तो जब एक सवाल दो तीन दिन हुये इस सदन में उठा था उसी वक्त हुआ था न सिर्फ हमारे विरोध पक्ष के लोग बल्कि हमारी सरकार के जो ट्रेजरी बेंचेज के संसद सदस्य हैं उन्होंने भी यह ख्वाहिश की थी कि इस विषय पर सदन में पूरी तरह से चर्चा हो ताकि देश के अन्दर जो स्ट्राइक की परिस्थिति हो गई है उसका सही उपाय ढूढ़ा जाए। मैं मानती हूं कि आडवाणी जी ने कहा कि 2 लाख 30 हजार टीचर्स का सवाल है।

(उपसभाध्यक्ष) (श्री हेच० हनुमन्तप्पा) पीठासीन हुए]

मैं समझती हूं कि यह सिर्फ दो लाख तीस हजार टीचर्ज का सवाल नहीं है जो यूनीवर्सिटीज और कालेज में पढ़ाते हैं बल्कि उनके साथ जुड़े हुये लाखों विद्यार्थियों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है और उनके परिवार का सवाल है, उनके मां-बाप का सवाल

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]

है जो उन से जुड़े हुए हैं और हमारे पूरे हिन्दुस्तान के भविष्य का सवाल है। मैं यह भी जानती हूं कि भविष्य के सवालों और हमारे देश के जो स्टुडेंट्स का भविष्य है और उनकी शिक्षा के बारे में जो सरकार की सीरियसनेस है उसको एक नजर में रख कर हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राव साहब ने एक नयी शिक्षा नीति बनाई और नयी शिक्षा नीति या प्रणाली बनाने के साथ साथ उन्होंने यह भी सोचा कि किस तरीके से हमारे देश में जो हमारे अध्यापक हैं जो टीचर्ज हैं उनके स्तर को कैसे ऊंचा किया जाये। अभी आडवाणी जी ने खुद ही फरमाया अपनी तकरीर में कि इस प्रोफेशन को पांचवें दर्जे का प्रोफेशन समझा जाता था। अगर कुछ नहीं कर पाये, इंजीनियर नहीं बन, डाक्टर नहीं बने, मैम्बर पार्लियामेंट नहीं बने या आई० ए० एस० नहीं बने, आई० एफ० एस० नहीं बने मालूम नहीं क्या क्या चीज नहीं बने तो टीचर बन जाएंगे। क्योंकि टीचर का वेतन कम था लोग जब कुछ नहीं कर पाते थे तो टीचर बन जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं समझती हूं कि यह बात सब के लिये सही तौर से लागू होती है। आडवाणी जी, हमारे देश में परम्परा है गुरु की जगह बहुत ऊंची थी और शिष्य का मुकाम था चाहे वह द्रोणाचार्य और एकलव्य हो या आज का हो।

उसकी अपनी एक जगह और अपना एक मुकाम मौजूद है। तो उस्ताद की जगह हमेशा खाली रहती है। यह जरूरी है कि इन्सान को जिंदगी गुजारने के लिये एक अच्छे वेतन की जरूरत होती है। कोई मुफ्त पढ़ाने वाला, डाक्टरी करने वाला या इंजीनियर नहीं मिलता है। इन्हीं सब चीजों को सामने रखते हुये सरकार ने यह कोशिश की कि हमारे टीचरों की तनख्वाह बढ़ायें और इसी लिये जो फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट है उसको सामने रखें तो मेरे पास जो पुराने स्केल्ज हैं उनके के लिहाज से भी मैं अगर यह कहूं कि मैंने अपनी जिंदगी की पढ़ाई खत्म करने के बाद जो शुरूआत की थी तो एक टीचर के तौर पर की, कालेज में, तो मैं यह समझ सकती हूं कि टीचरों के दिल में क्या भावना होगी क्या उनके ख्यालात हैं और उन चीजों को लेकर वे **(व्यवधान)** मैं आई० ए० एस० में जा सकती थीं पर गयी नहीं..... **(व्यवधान)** इसीलिये थे यह समझ सकती थी कि टीचरों के मन में क्या भावना होगी। मैं यह भी सदन के सामने बताऊंगी कि जब मैंने एक लैक्चरर के तौर पर नौकरी ली थी मध्य प्रदेश में, भोपाल में तो मेरी तनख्वाह थी 275 रुपये और उसमें से साल के साल हमारा इन्कम टैक्स भी कट जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उन दिनों और आज के दिनों में कितना फर्क है। अगर आज कोई लैक्चरर नौकरी के लिये दरखवास्त देता है और उसको जगह मिलती है तो उसको कम से कम 2200 पये से कुछ ज्यादा ही मिलता है। 2200 रुपये बेसिक है और सब मिलाकर 3--4 हजार रुपये की तनख्वाह उसको मिलती है। मैं यह जरूर मानूंगी.. **(व्यवधान)** कि रुपये की कीमत घट गयी है, महंगाई बहुत बढ़ गयी है मगर उसके बावजूद भी कोशिश सरकार ने यही की है कि जितने भी जो हमारे कस्ट्रेंटस हैं रिसोर्सेज के ऊपर उनको सामने रखते हुये भी इनकी तनख्वाहों में जो कुछ मैक्सीमम बढ़ोत्तरी की जा सके वह की जाये। आपने जो मल्टिप्लिसिटि आफ ग्रेडस की बात की तो मैं समझती हूं जहां आप कहते हैं दूसरी जगह ग्रेड्स की मल्टिप्लिसिटी को कम किया गया है वहां मुझे यह समझ में आता है कि कुछ ग्रेड्स अलहिदा हो गये हैं। वैसे तो लैक्चरर, रीडर और प्रोफेसर इन तीनों हिस्सों में इनको डिवाइड किया है मगर जो ग्रेड्स किये हैं वे 7 नहीं 6 हैं क्योंकि 7वां जो है वह एक फिक्स वेतन है और प्रोफेसर एमरेटस का है। उसका इससे ताल्लुक नहीं है। अलहिदा तौर पर उसको पेमेंट होती है। उसको

उनके साथ जोड़ना मैं नहीं समझती हूं कि ठीक है। 6 में ही उनको डिवाइड किया गया है और यह सिर्फ सरकार ने इसलिये किये हैं ताकि किसी भी जगह पर कोई स्टैगनेंसी न हो और हर एक को मौका मिल सके कि वह आगे बढ़े और उसको दूसरे ग्रेड में जाने का मौका मिल सके। तीसरी बात मैं यहां पर यह कहूंगी कि जो आपने यहां लफ्ज इस्तेमाल किया है डिवाइड एण्ड रुल की पालिसी का तो मुझे नहीं लगता है आडवाणी जी यहां इस मौके पर यह ठीक होगा कि डिवाइड एण्ड रूल की बात को लेकर आयें क्योंकि उनके बारे में ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करने वाले नहीं हैं, जो कुछ भी उनके बारे में सोचा जायेगा वह एक एक्सपर्ट्स कमेटी होगी जिसमें यकीनन ब्यूरोक्रेटस नहीं होंगे बल्कि दूसरे एक्सपर्टस होंगे जो यह तय करेंगे कि उनको आगे के ग्रेड में तरक्की दी जाये कि नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लैक्चरर, लैक्चरर ही रहेगा। लेक्चरर रीडर नहीं हो सकता।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : आडवाणी जी, आपके सवाल के जवाब में मेरे दिमाग में यह आता है कि मान लीजिये आप एक बहुत काबिल स्टुडेंट रहे हों और मैं एक बहुत नालायक रही हूं, मैं यहां 30 साल से नौकरी कर रही हूं मगर क्योंकि मैंने यह 20 साल से नौकरी की है इसलिये नालायक होने के बावजूद भी मुझे उच्च ग्रेड मिलता है और आप जैसे जो गोल्ड मेडलिस्ट हो करके, तरक्की करके आये आपको मौका न मिले और आप 20 साल तक वहीं रुके रहें तो आप समझिये कि आपके मन में क्या भावना होगी। सरकार ने ये एवेन्यूज खोले हैं कि अगर कोई ब्रिलियेंट स्टुडेंट है ज्यादा पढ़ा सके ज्यादा कोशिश करे तो उसको इन्सेंटिव मिलना चाहिये ताकि वह आगे के ग्रेड में जा सके और सिर्फ इस वजह से नहीं जाये कि 20 30 साल से कालेज में जिंदगी गुजारी है लेकिन उसे यह मौका मिल सके। वह काबिल है तो ओपेन कंपटीशन में आ सके और कोई रोकता नहीं है कोई 20 25 साल की सर्विस वाला है कोई 5-10 साल की वाला है सबके लिये दरवाजा खुला है ओपेन कंपीटीशन का जिससे ज्यादा कोशिश होगी और ज्यादा लोग जा सकेंगे। इसमें मैं समझती हूं कि हमारे बच्चों की तालीम के लिये बेहतरी होगी क्योंकि अच्छे लोग आगे बढ़ कर आयेंगे और पूरे हिंदुस्तान के लिये जो ओपन कंपटीशन होगा, तो पूरी रियासतों से लोग आकर प्रतियोगिता करेंगे और कालेज और यूनिवर्सिटीज में काबिल लोग आयेंगे और जिस नीयत से सरकार ने यह नई शिक्षा नीति बनाई है, उसको इसमें बढ़ावा मिलेगा।

मैं समझती हूं कि हम यहां यह बात छोड़कर कि हम किस तरफ से बोल रहे हैं, हमको यह देखना चाहिये कि हमारे देश के जो हजारों-लाखों स्टूडेंटस हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनके विषय में क्या सही होगा, उन चीजों को मद्देनजर रख कर हमें बात करनी चाहिये।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी मुझे मालूम है कि आज टीचर्ज स्ट्राइक पर जरूर हैं, मगर यकीनन जो हमारे टीचर्ज हैं, वह खुशी से स्ट्राइक पर नहीं गये होंगे क्योंकि जो टीचर होता है, उसके मन में मां बाप तो अपने बच्चों को पैदा करके कालेज और स्कूलों में भेज देते हैं, उनकी जिंदगी बनाना, उनके दिमागों को रोशन करना, उनको तालीम देना, यह टीचर और गुरु का काम होता है और वही उनके फ्यूचर को संभालते हैं। मैं समझती हूं कि जो कुछ आज मैं यहां पर हूं, यकीनन मेरे मां बाप के मेरे ऊपर कुछ एहसान हैं, मगर उसका ज्यादा हिस्सा मेरे उन तमाम टीचर्ज का है जिन्होंने मुझे स्कूल से लेकर कालेज तक तालीम दी और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस सदन में बैठ कर कुछ बात कर सकूं और उनके बारे में भी कह सकूं।

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]

तो मैं यह समझती हूं कि यकीनन उनकी कुछ असुविधायें होंगी, मगर जहां तक मैंने इस विषय पर गौर किया है, मुझे उसमें कुछ खास असुविधा नजर नहीं आई।

जहां तक 80 परसेंट और 20 परसेंट का सवाल है कि पे कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से इम्पलिमेंट करने के लिये सरकार को चाहिये कि 100 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एड दे, तो यह सरकार के देखने की जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि राव साहब इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि किस तरीके से जो पे कमीशन की रेकोमेंडेशन हैं, उनको पूरी तरह से म्पलिमेंट किया जाए और वह चाहे यहां से 80 परसेंट दें या 90 परसेंट दें या 100 परसेंट दें, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि राव साहब इस बात का खास ख्याल रखें. . (**समय की घंटी**)...सरकार इस बात का ख्याल रखे कि वह इम्पलिमेंटेशन जो उसका हो, वह किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हो जाये ताकि कहीं पर डिसपैरिटी न रहे।

श्री राम अवधेश सिंह : (बिहार): मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन्तप्पा): आप बैठ जाइये, अवधेश जी। नो क्लैरिफिकेशन।

श्री राम अवधेश सिंह :*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, I am not allowing you. A number of speakers are there. I am not allowing any interruption. ...(*Interruptions*)...

श्री राम अवधेश सिंह :*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Nothing to go on record. I have not permitted you ... (*Interruptions*)... It is not going on record.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : अवधेश जी ने मुझे नालायक कहा, तो मैंने तो यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझती हूं....(**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : गोल्ड. मडलिस्ट कहा ना ... (**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह गोल्ड मडलिस्ट हैं, लेकिन अपने आपको नालायक कहा ... (**व्यवधान**)

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : आपसे तो मुझे इसी बात की उम्मीद है कि आप मुझे नालायक समझेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं आपको नालायक नहीं समझता हूं।...(**व्यवधान**) उसमें यह डिमार्केशन करना तो गलत है।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : जहां यह कहा जाता है कि हरेक को— तो मान्यवर, कोई पाईपलाइन या ट्यूब तो है नहीं कि इधर से हम डालें और उधर से गोली वैसी की वैसी निकल आए। यह तो ग्रेडेशन होते हैं। इन्सान एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ता है और किसी भी सर्विस को देखें, तो सारे जो सर्विस में शामिल होते हैं वह पूरे के पूरे कोई आई० ए० एस० के हों, तो सब सेक्रेटरी लेवल पर तो रिटायर नहीं होते।

आप हम लोगों की मिसाल लीजिये कि हम लोग पार्लियामेंट में आते हैं पर सारे के सारे तो मंत्री नहीं बन जाते हैं, कुछ एम० पी० भी रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो कोई मंत्री नहीं बनता है, वह नालायक होता है। वह भी काबिल होता है, उसका भी योगदान होता है।

एक माननीय सदस्य : बदकिस्मती होती है।...(**व्यवधान**)

*Not recorded.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : उसकी भी ताईद नहीं करने वाली हूं। **(व्यवधान)** मान्यवर, मैं यह कहूंगी कि यह मसला ऐसा है कि इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिये और मैं उन लाखों टीचर्स से इस बात की ख्वाहिश करूंगी और हमारे जो विरोध पक्ष के लोग हैं जो उनके बारे में हमदर्दी रखते हैं और उतनी ही हम भी हमदर्दी रखते हैं, मुझे उम्मीद है राव साहब को भी उनसे उतनी ही हमदर्दी है क्योंकि उनका भी ताल्लुक कहीं न कहीं एजुकेशन से रहा है। हिन्दुस्तान में तालीम का जो शोबा है, जो एजुकेशन है उसका कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अहमियत नहीं दी गई हो ; जब पंडित नेहरू की सरकार थी उस वक्त जो उनके सब से ज्यादा करीब के दोस्त थे, आजादी की लड़ाई के रहनुमना मौलाना आजाद को उन्होंने वह महकमा दिया और आज भी राजीव जी की सरकार में उनके जो सबसे सीनियर मंत्री हैं उनको यह एजुकेशन का महकमा दिया गया है। आप को याद होगा जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी और यह सोचा गया कि कहां से हम अपने रिसोर्सेज निकाल कर अपनी डिफेंस पर खर्च करें तो उस जमाने में कृष्णा मेनन जी ने कहा कि हम कहीं से भी अपने रिसोर्सेज कम कर देंगे, पेट काट लेंगे लेकिन हम एजुकेशन के ऊपर कमी नहीं करेंगे। इसलिये कि अगर हम एजुकेशन में कमी करेंगे तो हम देश के हित में बहुत नुकसान करेंगे। तो जहां इतनी अहमियत सरकार ने दी है मुझे यकीन है, मैं इस्तेदा करूंगी, मैं उनसे अपील करूंगी हमारे जो टीचर्स हैं जो 2 लाख 30 हजार टीचर्स स्ट्राइक पर गये हैं उनसे मैं कहूंगी कि वे ठंडे दिल से सोचें कि सरकार ने जो कुछ बनाया है उनके हक में बनाया है, सरकार कोई उनकी दुश्मन नहीं है कि उनका कोई नुकसान करना चाहती है। अपनी तरफ से उन्होंने खुद रिकमेंडेशन दी है और महरोत्रा कमेटी के अन्दर कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे, महरोत्रा साहब खुद बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के एमीनेंट प्रोफेसर थे, वह भी इसी लाइन से आये थे, उन्होंने भी सोचकर किया होगा और मुझे यकीन है कि कोई प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर के हक में नुकसान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ राव साहब से ख्वाहिश करूंगी कि आप थोड़ा नरमी के साथ जैसा कि आप कर रहे हैं उन लोगों से बात करें और उनसे भी कहूंगी कि जो हजारों लाखों आवर्ज का नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये हम यहां यह सोचकर नहीं कि हम आपोजीशन से बोल रहे हैं या ट्रेजरी बैंचेज से बोल रहे हैं बल्कि यह सोचकर कि हम देश के हित में बोल रहे हैं और इसके लिये क्या सोचना चाहिये यह सोचकर ख्वाहिश करूंगी कि स्ट्राइक कल ही बन्द हो जाये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Hon. Members, there are 18 persons yet to speak on the subject. So, I request you kindly to take note of the bell and plan your speeches to be within your time so that everyone of you can take part.

SHRI V. GOPALSAMY: Only 18 speakers, but two-and-a-half lakh teachers are on strike.

DR. R. K. PODDAR (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, everybody has high regards for the hon. Minister, Mr. Narasimha Rao. But it is very curious that he has taken a very unreasonably rigid stand with regard to the strike by the university and college teachers, and to justify his rigid stand he has even taken recourse to inaccuracies in the statement he has made in the Lok Sabha, many of which have been pointed out by my esteemed colleague, Shri Advaniji.

Sir, what are the major issues? The major issues before the teachers, professors of colleges and universities are these: All over the world the usual gradation of the university and college teachers is, lecturers, readers and equivalent ranks. In the United States they call them Associate professors and professors. Why disturb these three grades, these three scales and make them 6 or 7 or 9! Please keep them as such. Recession has occurred, the cost of living has increased. So, you adjust the pay scales. That has been done. There is not much difference, not very much argument on the revised pay scales. While you have revised the pay-scales, you have put in

[Dr. R. K. Poddar]

certain conditions of service which is agitating the minds of all kinds of teachers. Even the teachers of prestigious institutions like JNU, Delhi University, Aligarh Muslim University, Calcutta University and Allahabad University, everywhere, they have opposed it almost to a person. There are a few of course, but they are an insignificant minority. Can all of them be wrong? So, I would request the hon. Minister to be a little more reasonable and not to pose the issue as a "take it or leave it" issue. Kindly see to it. In fact, you are trying to put the things in this fashion that already there are five grades. But you yourself know it very well that at present, there is a grade called senior lecturer in some universities. We don't have such a grade in Calcutta University. But senior lecturers are the same as the readers. They have the same scales as the readers have and the professor of eminence, which the university tried to introduce, not a single professor accepted it. It exists on paper but actually, these are three grades. Now, you have split up the lecturer scale into three grades reader scale into two and professor scale into two.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: No, readers also three. Now, there are only two grades in professor's scale two in reader's scale. Three were already two grades in the case of lecturers. They have been raised by one.

DR. R. K. PODDAR: No, senior lecturer is similar to reader.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Not senior, but selection grade. *(Interruption)* That has nothing to do with the normal run up. Keep it aside in both lists. Don't add this here, don't add it there.

DR. R. K. PODDAR: Now, these two schemes these new proposals that you have introduced, the major thrust is: you want to introduce a so-called caste system in the academic sphere. That means you want to give the promotional avenues to lecturers but keep them lecturers all their life Lecturers can be senior lecturers and selection grade lecturers as if you make some body a sudra and then a senior sudra and then a selection grade sudra but you never allow him to become a Kshatriya *(Interruptions)*. Now what was wrong with the current merit promotion? There is an observation regarding merit promotion in Mehrotra Committee Report as Advani Ji has mentioned. But, Sir, I do not want to elaborate but everywhere, the merit promotion cases were dealt with by the same Selection Committee like other selections. At least, in Calcutta, we had the same Selection Committee and Professors and Readers were selected by the same Committee as the open post. It may be that in the case of merit promotion, there were experts from the Chancellery experts appointed by the Syndicate, experts appointed by the Faculty. They were, perhaps, a little lenient. It could be possible and there could be other lapses there. I do not deny it. But the question is you have lapses in election also but do you propose that the election process shall be done away with? There is rigging in elections. For that do you say there shall be no election? We can sit around the table and can suggest or devise means in which we can make the merit promotion system foolproof. So, all the teachers want that the existing system be continued. Keep the existing merit promotion avenues intact and frame new rules. Everybody should think. It is a national question. It is not a party question or partisan question. All should sit together and devise rules which should be more foolproof. So, do not make the teachers appear as if they are shying away from evaluation, running away from evaluation system and they are the villain of the piece. If you point at the teachers, if you deny the teachers what they want, do you think everything will be all right? Do you think the condition of education in the country today is because of teachers? Are the teachers the guilty persons?

Regarding the 'Inverted Pyramid', a lot has been said. I do not repeat. I can only quote the latest figures with the University Grants Commission in 1984-85. What

does the All India picture show? Between 1980 and 1985, Professors and Readers were about 29 per cent in 1980. They are now 33 per cent in 1985. It was exactly the policy of the UGC to convert one-third of the Teachers to Readers and Professors, making promotions. What was wrong in it? The next question, a major question, on which the teachers are agitating is regarding the 100 per cent assistance to States to implement. This is a major issue which we should all realise very seriously. Even in the case of the 1973 Sen Committe, three States could not implement. It because they put up the argument, the usual argument, that they have constraint of resources. Now, if you continue this kind of working, the financial burden will be a lot more. So, only if the Centre takes 100 per cent responsibility for the new scheme at least for five years, uniformity can be ensured on the All India scales.

I would lastly request the hon. Minister not to stand on prestige. Kindly call a meeting. It could even be a tripartite meeting with the representatives of the teachers for which you can invite Members of both the Houses of Parliament from all parties. We could sit around and evolve a via media by which an honourable settlement could be arrived at.

Thank you, Sir.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी व सदन का ध्यान वर्तमान शिक्षक जगत की अराजकता के संदर्भ में अपनी प्राचीन शिक्षा की विरासत की ओर दिलाना चाहती हूं। अगर अपने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समृद्ध अतीत पर हम गौर करें तो पता चलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी बुनियादी और व्यावहारिक थी। शिक्षक के प्रति समाज में अत्यंत सम्मान का भाव था। उस परिवेश में गुरु और शिष्य की परम्परा अटूट थी। उस जमाने में गुरु का कोई नियम नहीं था क्योंकि गुरु स्वयं मूल्यों का नियामक था। इसीलिए गुरु समाज के लिए एक आदर्श था। ऐसे परिवेश में शिक्षित होकर एक शिष्य भी अपने गुरु की तरह अत्यंत प्रतिभाशाली, उदार और आदर्शवादी हुआ करते थे। ऐसे में ऐसे गुरु और शिष्य समाज के सामने भी एक आदर्श उपस्थित करते थे। जिसकी रोशनी समाज में एक नयी आस्था पैदा करती थी। अगर उदाहरण ही देना है तो ऐसे बीसियों उदाहरण गुरू शिष्य परम्परा के दिए जा सकते हैं। महर्षि पाणिनि, वरतन्तु, ऋषि द्रोणाचार्य आदि ऐसे ही गुरु थे जिनके ज्ञान की लौ ने हजारों शलाका शिष्यों को पैदा किया। उन्नीसवीं शताब्दी के उदय तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गहरी आस्था और उस स्रोत से ग्रहण करने की आदत थी। संस्कृत भाषा की ज्ञान परम्परा के महान गुरु आचार्य विरजानन्दब दण्डी का नाम अज्ञात नहीं है, जिन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे आर्य समाज के महान पथ प्रदर्शक को अपने संरक्षण में रखकर पढ़ाया-लिखाया। शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने स्वामी दयानन्द जी को उपदेश दिया कि 'मेरे योग्य शिष्य, आज पूरा देश घोर अंधकार में भटक रहा है। तुम मेरे योग्य शिष्य हो। मेरी इच्छा है कि तुम पूरे संसार में अपने ज्ञान की रोशनी बिखेर दो।' स्वामी दयानन्द जी ने जो कुछ किया - उससे आज पूरा देश और भारतीय समाज वाकिफ है, इसे बताने की जरूरत नहीं।

जाहिर है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं थी, न ही किसी राजाश्रय का दखल था। बल्कि पूर्ण रूप से गुरु इच्छा पर केन्द्रित थी। लेकिन क्या कारण है कि आज की शिक्षा व्यवस्था तमाम सरकारी साधनों व सुविधाओं के बीच उतनी विकसित और बुनियादी नहीं हो पा रही है जिसकी अपेक्षा थी। आज इसकी खोज करनी आवश्यक है।

बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया तो गुरु शिष्य की यह परम्परा एकदम से टूट गई। पूरे देश में व्यक्तिगत प्रयासों से चले रहे गुरुकुल टूट गए। संस्कृत भाषा सीमित वर्ग के लोगों के बीच चलती गई।

[श्रीमती वीणा वर्मा]

पूरे देश में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उन्होंने भारत के लिए जो शिक्षा व्यवस्था लागू की उसमें लार्ड मकाले की शिक्षा प्रद्धति प्रतिमान बनाई गई। ऐसे कठिन दौर में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के साथ सामाजिक मूल्यों में भी विघटन हुआ। उस महान परम्परा के गुरु की जगह एक वेतन भोगी कर्मचारी शिक्षक और घरों में पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए ट्यूटर का जन्म हुआ। जाहिर है कि इससे शक्षिक प्रयोजनों पर सीधा असर पड़ा। शिक्षा मात्र कायस्थों की जरिया हो गई। ऐसे में उस गुरु और शिष्य की परम्परा का पूर्ण खात्मा हो गया।

आजादी के इन चालीस वर्षों में हमारी शिक्षा व्यवस्था कमोवेश आज भी लार्ड मकाले की शिक्षा व्यवस्था से पूर्ण छुटकारा नही पा सकी। फलतः हमारे यहां उच्च शिक्षा प्राप्त युवक साक्षर होते है, शिक्षित नहीं। इन चालीस वर्षों में गौर से देखा जाये तो हमारे विश्वविद्यालयों ने छात्र और छात्राओं को महज साक्षर बनाया, उन्हें पूर्ण शिक्षित नहीं बनाया। यह आज एक निर्मम सच्चाई है कि अयोग्य छात्र इसीलिए पैदा हो रहे है क्योंकि योग्य शिक्षक हमारे विश्वविद्यालयों में बहुत कम है। अधिकांश विश्वविद्यालयों के हर विभाग में मिडियाकर और तृतीय श्रेणी की प्रतिभा वाले लोग शिक्षक का दायित्व संभाले है जिन्हें न तो अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी सिद्धातों का पता है और न ही आधुनिक जीवन की दिशा को नियंत्रित करने वाली नई शिक्षा व्यवस्था का।

फलतः पिछले दो दशकों में विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर बहुत गिरा है। पठन पाठन का महोल कई जगहों पर बिल्कुल समाप्त सा है शिक्षक अपनी गलत सही मांगों को लेकर साल भर कोई न कोई हड़ताल करता रहता है। जाहिर है इससे सरकार का अंकुश भी बहुत बढ़ा है। ऐसे सरकारी हस्तक्षेप के कारण आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था लगभग शिक्षा मंत्रालय की दीवारों में बैठे कुछ सीमित अधिकारियों के हाथों में आ चुकी है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को पूर्ण पूर्णतया एक वर्कशाप या कोयला खदान के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। यह रास्ता निश्चित रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक खतरनाक मोड़ है जिससे बचना आवश्यक है।

महोदय, 4 अगस्त से पूरे देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की हड़ताल है। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि शिक्षकों की हड़ताल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। शिक्षकों ने मेहरोत्रा समिति के वेतन और शिक्षकों के प्रमोशन संबंधी सभी सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है। इस तरह पूरा शिक्षक समुदाय आक्रोश और क्षोभ की सीमा तक पहुंच कर आज केन्द्रीय शिक्षा नीति के नए कदम का निर्मम आलोचक हो उठा है।

सवाल यह है कि उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए मंत्रालय का शिक्षा विभाग कैसे यह मान रहा है कि वह जो योजना बना रहा है, वह सौ फीसदी उचित है जब कि शिक्षा के लिए जिम्मेदार उपकुलपति, विद्वत परिषद्, शिक्षक सभी उस योजना को अस्वीकार कर रहे हैं। शिक्षकों की जो मांगें हैं उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे सौ फीसदी उचित है, लेकिन इतना तो है कि अपने देश का शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो, आकर्षक हो, इसकी जानकारी निश्चय ही शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक सचिवों से उन्हें अधिक है। आश्चर्य तो यह है कि महरोत्रा समिति ने इस प्रयोजन से जो अच्छी सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में की थी उन्हें अस्वीकार करके सचिवों ने फिलहाल जो साबित किया है वह शिक्षा के हित में नही है। और तो और जब मंत्रालय से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो अपनी ही रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर इसे वर्तमान रूप में पेश किये जाने से पहले हैरान प्रो० मेहरोत्रा ही हुए थे। शिक्षकों की हड़ताल के मुख्य तीन मुद्दे हैं:

लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर की तीन श्रेणियों में अध्यापकों को वेतनमान के जरिये विभाजित करना, उनमें वर्ग भेद पैदा करना होगा इससे उनका मनोबल गिरेगा।

हड़ताल का दूसरा मुद्दा है--सन् 1983 में सरकार ने जो मेरिट अवार्डस स्कीम लागू की थी उसे समाप्त करना उन पर कुठाराघात है। अध्यापकों के सारे सेवा काल में एक प्रोन्नति का अवसर न देना, निश्चय ही शिक्षा सचिवों की किसी मानसिक ग्रंथि का कारण है।

शिक्षकों की तीसरी मांग है--अध्यापकों के वांछित वेतनमानों और प्रोन्नति योजना को एक साथ सारे देश में लागू कराना। मेहरोत्रा कमेटी ने केन्द्र द्वारा दी जाने वाली शत-प्रतिशत सहायता के लिए सिफारिशें की थीं लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने इसे नामंजूर करके मात्र 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का राज्य सरकारों के लिए प्रस्ताव किया है जबकि सन् 1973 के वेतनमान भी अध्यापकों को नहीं दिये जा रहे।

देश में पहली बार 23,000 अध्यापकों की हड़ताल सामने है जिसका सीधा असर 34 लाख उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर पड़ा है। आमतौर पर देखने में ऐसा लगता है कि ऐसी हड़ताल का थोड़ा बहुत असर स्वयं अध्यापक और विद्यार्थी के अतिरिक्त किसी और पर नहीं पड़ता। पर अनिश्चित कालीन इस स्ट्राइक को यों ही होने देना और दरवाजे बंद करके बैठ जाने की सरकार की नीति बहुत अच्छी नहीं। अतः मैं एक बार फिर इस सदन के माध्यम से आप से कहना चाहूंगी कि इस स्ट्राइक के निराकरण के लिए जल्दी ही ऐसा कदम उठायें जिससे शिक्षक और सरकार के बीच संवाद का कोई विवेकपूर्ण रिश्ता कायम हो सके।

पिछले दिनों मानव संसाधन मंत्री जी ने शिक्षकों की मांगों को पूर्णतया गैर-वाजिब साबित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय में लौट आने की सलाह दी है, मुझे नहीं लगता कि शिक्षक इस तरह हथियार डाल देंगे बल्कि छात्रों ने व अन्य संस्थाओं ने भी इस हड़ताल का समर्थन देने का आश्वासन दिया है। जरूरत इस बात की है कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर एक बार फिर पुनर्विचार करे और जरूरी मांगों पर समझौते के जरिए ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे इस समस्या का कोई सार्थक हल जल्दी ही निकल सके। धन्यवाद :

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह कहूं कि आज के मानव संसाधन मंत्री का हमारे राज्य की कई शिक्षण संस्थाओं से निकट का संबंध है, इतना ही नहीं जब हैदराबाद का मुक्ति संग्राम चल रहा था और जिन लोगों के नेतृत्व में यह संग्राम चल रहा था उसमें आप भी एक थे तो कैलाशवासी स्वामी जी के साथ आपका बहुत निकट संबंध रहा और आज कई बहुत अच्छी संस्थायें मराठवाडा में चलती है जिन्होंने इस स्वतंत्रता मुक्ति संग्राम में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है एक नया वातावरण तैयार करने के लिये, एक नयी प्रेरणा देने के लिये, एक समर्थ शक्तिशाली सरकार के खिलाफ जूझने के लिये। मैं यह मानता हूं कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिये कोई एक नयी प्रेरणा, नया सामर्थ्य, नयी दिशा आवश्यक थी वैसे ही एक नया समाज बनाने के लिये नयी शक्ति और नयी प्रेरणा की आवश्यकता है। आप स्वयं जिस नयी शिक्षा नीति का अनुपालन इस देश में कराना चाहते हैं। नयी शिक्षा नीति को यहां लागू करके नये मूल्यों की प्रतिष्ठापना करना चाहते हैं, नये परिवर्तन की तरफ एक नयी प्रेरणा नवयुवकों में जागृत करना चाहते हैं, ऐसी ही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अगर इससे कहीं सहमत नहीं होता तो शायद मैं यह अपने प्रिलिमनरी भाषण में नहीं कहता। हम को इस बात का दुख है कि जिनमें पुराने मूल्यों की जागृति है और नये मूल्यों के लिये भी प्रयास करना चाहते हैं वैसे आप जैसे व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने अड़े रहेंगे यह हमारे समझ के बाहर की बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आम तौर पर शिक्षकों की स्ट्राइक के खिलाफ हूं मैं यह नहीं मानता कि शिक्षकों की कोई ट्रेड यूनियन बन जाये जहां पर ज्यादा दाम और कम काम की घोषणा की जाये। शिक्षक हमारे समाज का एक ऐसा अंग हैं जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बालकों को संस्कार देने का काम वे करते हैं। इसलिये जब कभी शिक्षकों की स्ट्राइक होती है तो आम तौर

[डा० बापू कालदाते]

पर मेरी राय यह रहती है कि जरा आप इसको देख लीजिये, बात कर लीजिये और अगर बात करके बात सुलझ सकती है तो वह काम कीजिये। जैसा मैंने कहा, अध्यापकों का काम संस्कार करने का है। इस स्ट्राइक के बारे में भी शुरू में मुझे लगा कि शायद कोई पैसे की बात है कोई आर्थिक सवाल हो, लेकिन जैसा आडवाणी जी ने कहा, इसमें पैसे की बात नहीं है। अगर वे कहते कि हमको आपने 4500/ रु० का वेतन दिया है, इसके बदले 6000/ का वेतन दीजिये तो यह एक दूसरी बात थी। लेकिन उनका कहना है कि पैसे के संदर्भ में वे यह संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जैसा आडवाणी जी ने साफ कहा कि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अपनी प्रतिष्ठा के लिये, शिक्षा की स्वायत्ता के लिये और जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये उन मूल्यों के लिये वे संघर्ष कर रहे हैं। जब अध्यापकगण 17 जुलाई, 1987 को आपसे मिले थे उस वक्त शायद डाक्टरों की हड़ताल चल रही थी। जहां तक मेरी जानकारी है, वह जानकारी गलत भी हो सकती है, जो कुछ रिपोर्ट आई है, ए० आई० एफ० यू० टी० ने अपनी मांग आपके सामने रखी। लेकिन आपने जो निर्णय लिये उससे शिक्षकों में निराशा पैदा हुई। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शिक्षकों का संबंध सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, उनका संबंध बालकों में संस्कार करने से भी है। अगर उनके मन में निराशा और कटुता पैदा होती है तो इसका असर समाज के दूसरे वर्गों पर भी पड़ेगा। यह कटुता विद्यार्थियों के अन्दर भी फलेगी। उसका परिणाम समाज के लिये अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षकों में कटुता और निराशा का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। पैसे के संबंध में कोई निराशा होती है तो उसका संबंध अध्यापकों तक रह सकता है, लेकिन उनके आत्म-सम्मान का प्रश्न हो तो इसका संबंध पूरे समाज से होता है। यह बहुत गंभीर बात है। इस संबंध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, आडवाणी जी ने आपके सामने बहुत से प्रश्न रखे हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूं। इस संबंध में यह कहा गया कि इस मामले का संबंध राज्य सरकारों से है। यह भी कहा गया कि राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। मैं इन सारे सवालों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना हूं कि यह कहा गया है कि राज्य सरकारें चाहें तो ये वेतनमान दे सकते है चाहे तो कम वेतन भी दे सकते हैं। दूसरी बात राज्य सरकारें चाहें तो 1-1-86 के बाद भी दे सकती हैं। यह गलत होगा। शिक्षकों की क देश में एक माहौल बनेगा और उसका असर भी अच्छा पड़ेगा। ग्रेडस के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि ग्रेडस से मुझे डर लगता है फेवरिटिज्म का। जितने ही ग्रेड बढ़ते जायेंगे उतनी ही इसकी संभावना ज्यादा होगी। क्योंकि शिक्षा संस्थानों को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आफ्टर आल वी कम फ्राम दि सेम मासाइटी। हम मे भी और सब शिक्षकों में जो लोग हैं वे दूध के धोये हैं ऐसा मैं खुद नहीं मानता हूं। लेकिन हमको ऐसी मदद करनी चाहिए जिससे उसमें ज्यादा खराबियां न आयें। इस में कम से कम खराबी आये इतनी ही बात हो सकती है। अगर हम, उनकी जो मांगें है, जो ग्रेड वे चाहते हैं उनको रखकर उनकी मांग अगर पूरी करें तो इसमें मदद हो सकती है। इससे उसमें जो भी फेवरिटिज्म हो वह भले ही होता हो तो भी हम यह बात कर पायेंगे। इसलि मेरी यह मांग है उनकी मांगो को मानकर इस बात को समाप्त करें।

लास्ट में, मेरी समझ में नहीं आता, हम सब लोगों से बात करते हैं तो इन लोगों से बात करने में क्या बिगड़ता है? आज तक इनसे बात क्यों नहीं हुई। आपने कहा कि क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी इसलिए बात नहीं हो सकी। उन्होंने पहले ही अनाउन्स कर दिया था कि हम चार तारीख से सट्राइक पर जा रहे हैं। यह अच्छा होता अगर 4 तारीख से पहले उनसे बात हो जाती यह मैं मानता हूं। 15 दिन बीत गये और इससे अधिक दिन की स्ट्राइक शिक्षा की दृष्टि से अच्छी नहीं हैं हमें उनके मन में निराशा और कटुता की भावना को रोकना है। इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनसे बात करें और जो भी समस्यायें

उन्होंने आपके सामने रखा है उनको सुलझाने का प्रयास करें ताकि जिस दिशा में आप देश को ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जाने में वे सक्षमता से काम कर सकें।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, a very serious situation has arisen in the country because 2,30,000 university teachers have gone on strike from 5,600 colleges and 150 Universities. The strike is going on since 4th August, 1987. As my other friends have already stated, 34 lakh students have been badly affected.

Sir, I have a triangular outlook towards this problem. The first thing is that there is an impression that a man goes to the profession of teaching either as a school teacher or a college teacher if he does not get employment anywhere or he misses all the technical lines. It is not correct because there are some inherent defects in this and the outlook of the society towards education is not very constructive till today. Sir, my Government has brought the New Educational Policy and we have tried our level best to standardize education and the educational manpower. And for that purpose, we have started the Human Resource Ministry. We have accepted the R. C. Mehrotra Committee Report and we have tried to remove the disparities in the salaries. Though we have created seven grades in the teaching line in the colleges and universities, the salary or the pay for the Lecturer previously was Rs. 700 to 1600 and now they have a pay scale of Rs. 2200—4,000. Then, for the Senior Lecturer which was not existing at all earlier, the scale of pay is Rs. 3,3000—5,000. Then for the Lecturer (Selection Post), there are three grades. Earlier it was Rs. 1200 to Rs. 1900. Now it is Rs. 3,700 to Rs. 5,300. The same grade is there for the Reader. For the Professor it was Rs. 1500 to Rs. 2,500. Now it is Rs. 4,500 to Rs. 7,300. For the Professor of Eminence, it was a fixed salary of Rs. 3,000. Now it has become a fixed salary of Rs. 8,000. Sir, if I may mention I was also a Demonstrator once. I rose from the post of Demonstrator to the grade of Professor. I was employed on a monthly salary of Rs. 90. Including allowances, I was getting just Rs. 180 per month in 1962. And when I resigned as Professor, I was getting a basic pay of Rs. 800. I was getting some Rs. 1200 in total. When I compare those grades with the present grades, I feel that we are giving tremendous salaries now. But at the same time we must see how the professors are working in the colleges, how many periods they take and how much work they do. If you go towards the universities and the colleges and have a look at them, you will find that not a single professor is taking more than three periods in a day and not more than 25 to 26 periods in a week, though our UGC has prescribed more than 60 or 70 periods a week, we are paying them the salary of more than Rs. 7600. What will the common man of this country think about these professors? I will not mind if we give them Rs. 10,000. But when we look towards our economic situation, when we look towards the standard of our common man, then these salaries are too high. This is one side of the picture.

Secondly, Sir, when we look towards some other officers, we see that they are getting high salaries. I am of the view that a college professor or teacher has better merit than that of an IAS officer.

So, what I would like to suggest is that at the time of selection, the selection process should be such that it is harder and stricter for the lecturer and the professor and it should be equivalent to that of the IAS officer. It will not be possible to get that quality of people but we must have the training facilities. The Ministry of Human Resource Development must put in its efforts to prepare such manpower, educational manpower so that our future generation which is coming in this country is of a better quality.

Sir, when we look towards the grade of a lecturer, we see that in five years the salary of a lecturer is Rs. 2500, while as an IAS officer at the end of five years gets Rs. 3200 plus a special pay of Rs. 500. A lecturer in the ninth year gets Rs. 3000 and an IAS officer gets Rs. 3500 plus a

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]

special pay of Rs. 500. At the end of 13th year, a lecturer or Reader will be getting Rs. 3500 and an IAS officer will be getting Rs. 4800 plus Rs. 500 as special pay. That is the disparity. Then an IAS officer can go up to the level of a Secretary also. I do not agree with the Hon. Minister that having seven or eight greades is more advantageous. As I see, we must have only three grades for lecturers, readers and professors. But at the time of the selection you must be very strict and see how a lecturer is to be appointed. But at the time of fixing the salaries we must have some equilibrium with the salaries of other bureaucrats and officers. I know except the IAS officers all the other officers are geting very low salaries. Sir, there is nothing very unnatural or very divine about the quality of IAS officers that they are given very high salaries. I have seen so many IAS officers who do not know so many things. The man who goes to the district as an IAS officer, he commits so many blunders and indulges in corruption either under the Employment Guarantee Scheme or under the NREP or the RLGP. He commits so many mistakes, he indulges in corruption and he gets the highest salary. That disparity should be removed. (*Interruptions*) Somebody else may also be the agent of an IAS officer. Sir, what I mean to suggest is that we must have some machinery whereby there can be equality in pay.

Sir, the other thing which I would like to suggest is that there should not be multiplicity of grades. The multiplicity of grad have been opposed by the Kothari Commission and other committees. Multiplicity of grades should not be there. There should be only three grades for lecturers, readers and professors.

Sir, in some of the universities, in Calcutta university and some other universities there is a rule that after six years' of service a lecturer can become a reader and after eight years a reader can become a professor. These things are there. There should be some fixed period after which a lecturer is promoted as a reader and a reader is promoted as a professor. Then the lecturers must have some refresher training and they should be able to train their students. All the problems in the country today are due to education only. When I look towards the functioning of my university, the Marathwada university, my esteemed colleage, Dr. Bapu Kaldate, and Hon. Minister, Shri Narasimharao also come from there, I am not happy. And when we visit that university, we feel ashamed. There are so many cases of corruption. Hundreds of such cases are going on in the High Court Bench at Aurangabad. So, we should see to it that corruption from the universities is totally rooted out and that should be our first priority, because unless we can remove corruption from educational system, our total national life cannot be purified.

Lastly, we are giving very high salaries to the Professsors. It must at he same time be ensured that they do full justice to the work, either of teaching or research and if anybody is found unsuitable, his services should be immediately terminated. We must not allow dirty politics to remain in our educational system.

I would conclude by quoting Pandit Jawaharlal Nehru:

"पंडित जी ने कहा था: हर इन्सान अपना हक मांगता है। हक मांगना ठीक बात है। मगर साथ-साथ उनका कोई फर्ज भी होता है। जो इंसान अपना फर्ज पूरा नहीं करता वह हक भी मांग नहीं सकता।"

PROF. C. LAKSHMANNA: (Andhra Pradesh): I rise to speak with any amount of sadness, because I understand the psyche of the University and college teachers, for I had been one myself for the last 25 years or so. I know, no University teacher or a college teacher would like to be on the roads, much less to demonstrate before the Government for their legitimate rights. But nonetheless, lakhs of teachers spanning over 150 Universities and about 5000 to 6000 colleges are today agitating for what has been their legitimate right which nas been denied to them.

There are three main points of contention about which a mention has been made already, and I will start with the last point first, namely, need for giving cent per cent assistance to the States so that they can implement the scales with effect from 1-1-1986. This date has been accepted for implementation of the scales. Respected Minister, Shri P. V. Narasimha Rao says that he talked to the Ministers of the States and they are likely to agree to implement the scales even with 80 per cent grant from the Centre. I would like to agree with him on the face of it, but I would remind him that a State like Kerala has not implemented the scales so far and if the Minister tells me that he will be able to persuade such governments to implement even with 80 per cent grant from the Union Governmment, it is some thing which I will not easily bite. That is the reason why Mehrotra Committee has categorically recommended that there has to be cent per cent grant given to the State Governments so that they can implement from the same date on which it is implemented by the Central Universities. But unfortunately, the Minister is adament on this. He is also adament on another point which creates differences between one set of Universities in one State and another set of Universities in another State, regarding notional fixation of the orades. I will not go into it because different States are giving different rates of D. A. and the new scales take this into consideration. Therefore, a Professor in one State may have to be fixed at a much lower salary than the one in some other State. Nonetheless, Union Government has rejected that also. I request the Minister to consider these two issues.

Then I come to the important issue, namely, multiple pay structure and also promotions.

Again, here, I will start with merit promotion, the scheme that was available earlier. What is humiliating is that on the one hand, Government feels that the merit scheme is not to be encouraged because it does away with the evaluation process which I contest. On the other hand, the Union Government says that if they still want merit promotion, they can opt for old scales. In this connection I would like to correct the Minister regarding evaluation. I had been associated with the merit promotion of professors, lecturers and readers in different universities. I would like to bring to the notice of the hon. Minister the process involved in the merit promotion evalnation. Unlike the normal promotion for readers and professors through the selection committee, in the case of merit promoion, evaluation is done by two more people because the bio-data of the candidate concerned is sent first to two experts who give their opinion regarding the suitability or otherwise of the teacher concerned. They put in a seal and send it to the selection committee. This selection committee which is constituted for the purpose of readers or professions as the case may be is the same as the one which is constituted for merit promotion also. In the case of regular selection for readers or professors, here is an advertisement and this is an advertisement which is meant for all, over the country; what is known as all-India merit basis. Excepting this particular clause, in the case of meril promotion, all other steps for evaluation are being followed, have been followed and this —this is the strength of the merit promotion scheme. Therefore, if the hon. Minister says in the other House or elsewhere that teachers do not want the evaluation programme, I do not agree with it. I contest it. The existing merit promotion does take the evaluation process into consideration as explained earlier.

The second point is, in the existing scheme, a person with ten years and Ph.D. or M.Phil. or a person with 15 years experience without Ph. D. could be considered for promotion and after selection, he becomes a reader. This means, in the existing promotion scheme, for a teacher, an avenue was available which was based on evaluation. An avenue was available after ten or fifteen years as the case may be. But now, to attain the same scale, which is equivalent to the scale of a selection grade lecturer, he has to wait for 20 years. Even from this point of view, I think, there is injustice done to the college

[Prof. C. Lakshmanna]

and university teachers. A person who is appointed as a lecturer can become a senior lecturer only after eight years by which time he would have a Ph. D. which was not the earlier case or at least M.Phil. and other conditions. After having become a senior lecturer, he has to wait for another 12 years before he could be considered for the post of selection grade lecturer. The scale of selection grade lecturer and the scale of reader has the same start. Therefore, what could have been attained under the merit promotion scheme in about ten or fifteen years, now, even to become a selection grade lecturer, not to speak of the designation, one has to wait for 20 years. I think, no natural justice can ever allow such a thing to happen. We have progressed in time. There cannot be any regression in terms of the facilities that are available in the profession. As per the 1973 scales and subsequently under the merit promotion scheme, a lecturer could become, as I was mentioning, a reader in about ten or fifteen years. Now, he has to wait for twenty years to become a selection grade lecturer. Then, what is the advantage of going through this three plus two plus one; six grades? In the case of the second one, it was not recommended; it was added by the Ministry. What is the logic? What is it which is being achieved as a result of this? If somebody could explain to me that by changing the grades from three to six, this is the type of additional justice, this is the type of meaning, being achieved, I am ready to accept it. But I do not think so. Nonetheless we are now wanting to have six grades instead of three. The recommendation and the consistent demand of the university and college teachers and educationists all over had been to reduce the grades to two. In fact in the Third or Fourth Plan scales we had only two scales—Assistant Professor and Professor. Only when we came to the 1973 scales, or a little before that, we came back to three grade system. From there now we want to go to six grade system. Therefore, I would like to appeal to the Minister to kindly consider this.

Then what is the rationale in having any new scheme? A new scheme, if it is introduced, it is to benefit the ultimate product—the ultimate product being the student. Now if the student is kept in mind and if we consider the teacher as the pivot round which the student community has to be built in the educational process, then what is the strength that is being created in the system which the ultimate product, namely the student, will get out of it? I do not see any. Therefore I would like to request the Minister to kindly consider this.

Apart from this, another thing which has been continuously contested by the teachers—and which was conceded in the 1973 scales—is the parity with the bureaucrats. What is the reason for the parity? The reason for the parity was this that the university teachers' position being scaled down, there was a natural erosion of talent from the teaching positions. Therefore we had to attract it to teaching. If that is the case, the parity would have been maintained. Now, as I was mentioning, if somebody starts as an IAS officer or an IFS officer on the one hand and as a Lecturer on the other, which is the same starting point, in about 17 years' time, the difference in pay between the IAS officer and a university teacher will be about Rs. 1900 and if we add Rs. 500 which is added as Special Pay when once they go into first promotion, the difference will be about Rs. 2400. Therefore on the one hand, we want to have an educational system where all good people should come, they should be continuously equipping themselves with acquisition of degrees by publications, by producing research projects, programmes and papers, Ph.D. and so on and so forth, on the other hand when it comes to the question of giving scales, we are hesitating. Therefore, I would like to once again ask as to how you are going to attract the talented people into education so that they, in turn, will create the cream which will have to occupy several positions, including that of IAS officers. Therefore I appeal to the Minister to kindly consider these three legitimate, genuine and good demands of the teachers and prevent any further their being out of colleges and universities, their

being on the road, thereby depriving lakhs and lakhs of students who should have been in the classes but who are not in the classes because the teachers are not there. And all this can happen only if the Minister gives up his present stand. I know this is the first time he has taken such a stand. I had the privilege of knowing him for the last 25 years. He was our Education Minister in Andhra Pradesh State. He has been Education Minister here. He has been our Chief Minister and he has been in several other capacities. I do not know why there is a new streak in him, of adamancy. Why is it that he is being so adamant in not opening a dialogue with the striking teachers? I asked him the other day, when did they give you the strike notice? How many attempts were made by them to reach you? How many times could you meet them? If you could not meet them, what is more important than meeting 2 lakh 30 thousand teachers and through them lakhs and lakhs of students? I do not know the reason but, nonetheless, the Minister has been very adamant. Therefore, I once again appeal to the Minister to kindly open the dialogue, discuss with them, try to convince if there are some points on which you can convince them. But go with an open mind to get convinced. In this process, kindly shake off whatever little influence the bureaucracy has, perhaps, exerted on you. It is my appeal because I am not in the habit of stating things which can be contested. Otherwise I could have cited what a particular bureaucrat said in an interview: I do not want to cite that. I appeal to you: Kindly shake off what little influence that has come on you from the bureaucratic hold—which is not good for the educational process. If you do that and if you accept whatever are the legitimate demands of the teachers who have been agitating for the last 14 or 15 days—and thereby causing loss of so many man-days for the teaching community as also for the students—I think you will be doing a great service to the educational process in this country. Thank you.

डा. रत्नाकर पांडेय : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, मेहरोत्रा कमेटी के संदर्भ में जब प्रश्न सदन में आया था तो माननीय नरसिंह राव जी ने आग्रह किया था कि इस पर एक डिबेट होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि आज यह माननीय सदन इस महत्वपूर्ण सामयिक समस्या पर विचार करने के लिए अपने निर्भीक और स्पष्ट मत को अभिव्यक्त कर रहा है। जहां तक मेहरोत्रा कमेटी की रिपोर्ट का प्रश्न है, हमारे माननीय अनेक विरोधी दल के मित्रों ने आरोप लगाया कि आज ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलने की कोशिश की जा रही है। ...(व्यवधान)...बिल्कुल कहा गया है, मैंने नोट किया है, किसी सदस्य ने कहा है। मेहरोत्रा कमेटी की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और उसमें साफ लिखा हुआ है :—

"समिति ने एक ऐसी योजना की सिफारिश की है, जिसके अनुसार हर प्राध्यापक को अपनी नौकरी के दौरान अतिरिक्त योग्यताएं अर्जित करने के साथ ही संतोषजनक कार्य-मूल्यांकन रिपोर्टों के होने पर दो पदोन्नतियां अवश्य मिल जायं। समिति ने कुछ चुने हुए कालेजों में रीडरों और प्रोफेसरों के पद बनाने का भी सुझाव दिया है। समिति जोर देकर कहना चाहती है कि रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर हमेशा अखिल भारतीय आधार पर चयन होना चाहिए।"

मैं जानना चाहता हूं माननीय... (व्यवधान)...

श्री रामअवधेश सिंह : इसमें आपको ब्यूरोक्रेसी नजर नहीं आती है।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Don't interrupt, please. Please don't answer any interruption.

डा. रत्नाकर पांडेय : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय आधार पर चयन की प्रक्रिया आपकी नई शिक्षा-नीति में रहेगी या सिविल

[डा० रत्नाकर पांडेय]

सर्विस में जैसे आप परमोशन देते हैं, उस तरह से भारत की नई शिक्षा-नीति चलाना चाहते हैं, आप पर यह दायित्व डाला गया है ? मैकाले ने 1827 में जो क्लर्क बनाने का कारखाना पैदा किया उसके बाद स्वतंत्र भारत में 39 वें वर्ष में एक नए ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया, जिसने नई शिक्षा नीति पर, जिसने अपनी योग्यता के अनुरूप बिना डिग्रियों के काम मिल सके, सोचा और आप चयन की प्रक्रिया को आल इण्डिया कंपीटीशन से मिटा करके परमोशन की स्कीम चलाना चाहते हैं या इस तरह का कंपीटीशन का काम करना चाहते हैं? इस देश की प्रतिभाएं जो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक आगे तक हैं, उनको अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने संस्कार के आधार पर अपनी योग्यता निर्धारित करने का स्थान मिले चाहे वह लेक्चरार हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे रीडर हो, चाहे और कुछ हो, उसके संबंध में कहा गया कि जिसको कोई काम नहीं मिलता, वह शिक्षक हो जाता है। मैंने बीस वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्रों में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और प्रिंसिपल के रूप में काम किया है और मैं जानता हूं कि संसद सदस्य भी यहां आते हैं, वह भी हाजिरी लगाते हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक कहीं पर रजिस्टर में एण्ट्री नहीं करता है, वह इसे अपमान समझता है। वह सोचता है हम क्यों अपनी उपस्थिति दाखिल कराएं, इसमें अपना अपमान समझता है। आप करना क्या चाहते हैं ? आपने नई शिक्षा-नीति में चार बातों पर जोर दिया है—विकेन्द्रीकरण, सहयोग, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस सदन में कि एक ओर जब आटोनोमी की बात चलती है तो दूसरी ओर एकाउंटेबिलिटी की भी बात चलनी चाहिए। एक ओर जब नियम और कानून की बात होती है तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कनवेंशन की बात करता है। कोई-न-कोई होल है जिससे वह बचकर के अपनी शर्तें मनवाना चहता है। नरसिंहराव जी मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आज सारे देश के लाखों टीचर्स ने स्ट्राइक की है। एक चैलेंज आपके सामने है। जहां तक टीचर्स से बात करने का सवाल है, पिछली हड़ताल का वाकया मुझे याद है। दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय कपूर साहब उसमें पड़े और टीचर्ज ने अपने मन से बना लिया समझौता उन्होंने अखबारों में पढ़ा मुझे भी अनुभव है। कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर जबरन मनवाने लगते हैं। कोई एक व्यक्ति चाहे यू० जी० सी० का चैयरमैन हो, चाहे सेक्रेटरी हो या मिनिस्टर हो एक साथ सब से बात नहीं कर सकता। कोई एक प्रतिनिधि अध्यापकों का आकर के बात करे नाकि सामुहिक रूप से सभी यह थेट करने की प्रवृत्ति यदि बंद नहीं हुई तो नई शिक्षा नीति का क्या होगा इस पर भी हमें विचार करना होगा।

एक बात कही गई है कि मेहरोत्रा कमेटी में एक भी शिक्षाविद नहीं हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं इसे पढ़ देता हूं—प्रोफेसर आर० सी० मेहरोत्रा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसर रहे है श्री सईद हमीद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं, डा० डी० एम० नंजुनदप्पा (कर्नाटक सरकार में संस्थागत वित्त विभाग) कर्नाटक विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं, डा० (श्रीमति) वनाजा आयंगर, जोकि श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपित की कुलपति हैं, श्री आनंद स्वरूप गोविंदवल्लभ पंत यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टैक्नालोजी में कुलपति रहे हैं, प्रोफेसर एन०एम० स्वनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक हैं, प्रोफेसर एस० रामशेषन, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के निदेशक हैं, प्रोफेसर जी० एस० भल्ला कृषि मूल्य आयोग, प्रोफेसर सी० मांडे नागपुर विश्वविद्यालय, उपसभाध्यक्ष जी मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इसमें इतने सदस्य हैं जिसमें कि एक भी ब्युरोक्रेट नहीं हैं। सारे-के-सारे शिक्षा जगत के लोग हैं। इसलिए मैं नाम पढ़ रहा हूं। प्रोफेसर आर० के० पारिम, कला, इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र

विभाग बड़ौदा, प्रोफेसर श्रीमति अनिता बनर्जी जादवपुर विश्वविद्यालय, डा० के० एन० उडुप्पा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय श्री ग्लाडविन एम० राय, प्रधानाचार्य सेंट जोंस कालेज आगरा, श्री आर० के० छाबड़ा एक्स सेक्रेटरी, यू० जी० सी० संयुक्त सचिव, शिक्षा, डा० श्रीमति लतासिंह, सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसके अलावा जो एस० जी० महालिक संयुक्त सचिव, वित्त, प्रोफेसर एस० के खन्ना यू०जी०सी० के सचिव हैं। इसका मतलब यह है कि सारे देश के शिक्षाविदों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस मतलब से मैंने इतने विस्तार से नाम पढ़े हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यापक और समाज के बारे में जो मंतव्य दिया गया है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह मंतव्य अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक संगठन परिषद का है। इसमें बताया गया है कि "अध्यापकों को चाहिए कि वे इस बात को मानें कि शिक्षा एक प्रकार की जनसेवा है। उन्हें चाहिए कि वे अपनी संस्थाओं के शैक्षिक कार्यकलापों से जनता को अवगत कराते रहें। समुदाय में शिक्षा संबंधी सुधार लाने के लिए कार्य करें और समुदाय के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करें। सामाजिक समस्याओं की जानकारी रखें और ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें जो समाज की उन्नति और उसके माध्यम से पूरे देश की उन्नति में सहायक हों।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज टीचर्स के नाम पर बहुत से राजनीतिक पार्टी के वर्कर्स हैं जो कि शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, बहुत से विदेशी कार्ड होल्डर हैं मैंने पहले भी कहा है और पुनः उसको दोहराना चाहता हूं कि जब तक एसोसिएशनबाजी और यूनियनबाजी बंद नहीं होगी चाहे वह टीचर्स की हो, चाहे छात्रों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो तब तक आप नई शिक्षानीति का कार्यान्वयन कर सकेंगे इसमें मुझे संदेह है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर एजुकेशन को एसेनसिएल घोषित करने का निर्णय किया है। क्या आप भी यह करेंगे। जब तक आप तीन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप नई शिक्षा नीति का कार्यान्वित और इतने बड़े समुदाय की जो हड़ताल की समस्या है उसको हल नहीं कर पाएंगे।

80 परसेंट सेंटर देगा और 20 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट दे, यह सेकेण्डरी है। इसमें कुछ दर्जन करोड़ रुपए का मामला है। मैं तो मांग करूंगा कि जब तक शिक्षा को ऐसेंसियल सर्विस आप नहीं बनाते हैं, तब तक शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, शिक्षा आत्म साक्षात्कार का साधन है, एकाग्रता आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब तक इस देश में दृढ़ संकल्प होकर अध्यापक कार्य नहीं करेगा, छात्र एकाग्रचित्त होकर अध्ययन नहीं करेगा, तब तक शिक्षा की समस्या हल नहीं हो पाएगी।

महोदय, पिछली बार आंदोलन हुआ था तो उस समय नो वर्क नो पे का सिद्धांत जिस दिन डिलिवर किया गया था उसके तीन दिन के भीतर हड़ताल खत्म हो गई। हर चीज में हम सबमिशन करेंगे, हर चीज में सरेन्डर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या शिक्षा मंत्रालय में आज इतनी हिम्मत है कि वह हड़तालियों की सर्विस ब्रेक करे, नो वर्क नो पे डिक्लियर करे? श्रीमन्, एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था टेलीविजन में शिक्षा के संबंध में किसी गार्जियन महिला ने कहा..."अध्यापक ब्लेकमेल इस हड़ताल से कर रहे हैं।"

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमंतप्पा) : पांडे जी, कृपया कंक्लूड कीजिए।

DR. RATNAKAR PANDEY: I am going to conclude within three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, please conclude in one minute.

DR. RATNAKAR PANDEY: Then, how can it be done? If you don't allow, I can sit.

[डा० रत्नाकर पांडेय]

श्रीमन, मैं कह रहा था कि नो वर्क नो पे अगर लागू करना है तो उसमें विलम्ब मत कीजिये । लेकिन अध्यापकों की हर शर्त हम जो चाहें वही करायेंगे, यह नीति घातक है, राष्ट्र के लिये घातक है, आने वाली पीढ़ियों के लिये घातक है ।

महोदय, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में वह है मल्टिप्लिसिटी आफ ग्रेडस । 7 ग्रेड आपने बनाये हैं । मैंने खुद अपनी अध्यक्षता में कम से कम सवा सौ लोगों को अपने कालेज में लैक्चरर पद से सीनियर लैक्चरर और रीडर बनाया है । माननीय सदस्य ने मेरे प्वाइंट का जबाव नहीं दिया कि कितने सीनियर लैक्चरर बनाये गये सैकड़ों रीडर हुये हैं और प्रोफेसर हुये हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गुरु की बहुत बड़ी महिमा है । हमारे यहां कहा गया है--

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पाय,
बलिहारी गु आपनो जो गोविन्द दियो बताय ।

मां-बाप तो बच्चों को पैदा कर देते हैं, लेकिन उसका संस्कार अध्यापक करता है । अध्यापक राष्ट्र का दिशा निर्देशक होता है । हमारे यहां चाणक्य जैसे अध्यापक हुये जिन्होंने चन्द्रगुप्त को शासक बनाया, वह चटिया बांधकर झोंपड़ी में रहता था । गुरु के बारे मे कहा गया है--

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु,
गुरुः देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात परमब्रह्म,
तस्मै श्री गुरवै नमः ।

गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, गुरू ईश्वर से बढ़कर माना गया है । लेकिन आज वह अपनी शर्तों पर काम करना चाहे तो उससे क्या आशा की जा सकती है ? गुरु का जीवन त्याग और सत्य का जीवन होता है । अध्यापक समाज को नई दिशा, नई रोशनी दे सकता है । ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या चाहता है यह हमेशा के लिये स्पष्ट हो जाना चाहिये । सरकार क्या चाहती है, अध्यापक क्या चाहता है और छात्र क्या चाहता है, इसका पता लगाने के लिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस के लिये गंभीरता से सोचें । जब पढ़ाई आरम्भ होती है तो धमकी दी जाती है कि हम हड़ताल करेंगे जब परीक्षा होनी है तब हड़ताल होती है, इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी । मेरी यह स्पष्ट मांग है कि शिक्षा को एसेंशियल सर्विस बनाया जाय और उसके लिये ऐकाउंटेबिलिटी अवश्य फिक्स की जाये ।

SHRI K. MOHANAN (Kerala): What are your views regarding the University teachers strike? What is your point, I would like to know. The discussion is regarding the University teachers strike. You have delivered a very good speech. I accept it. But the point is, precisely what is your point and what is your opinion regarding the University teachers strike?

DR. RATNAKAR PANDEY: My points are very, very clear.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Mohanan, the House has no time to reply to your questions.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुये कहना चाहूंगा कि शिक्षा का व्यावसायीकरण रोकिये और जो ट्रेड यूनियन का ट्रेंड है इस पर एक बार पूरा सदन गंभीरता से विचार करे । क्या शिक्षा को भी लेबर यूनियन बनायेंगे ? कल्याण परिषदें हों, वेलफेयर बोर्ड हों, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसमें लोग रहें काम करें और उनकी समस्याओं का हल हो । लेकिन इसको लेबर यूनियन बनाकर छोड़ दिया गया तो सारे देश में जो हड़ताल चल रही है वह निरन्तर चलती रहेगी । बड़ी कड़ाई के साथ अगर नयी शिक्षा नीति का जो चैलेंज सारे देश की ओर से आया है मंत्री जी अगर आप उस चैलेंज को मीट न करके, उसका मुकाबला न करके, उस चनौती का मुकाबला न करके पलायनवाद और एस्केपिज्म की नीति अपनाई तो मैं पुनः कहूंगा कि

हमारी नयी शिक्षा नीति का जो 1827 के बाद नया चिन्तन शुरू हुआ राष्ट्र में और जो सारे विश्व को एक नया जीवन दर्शन दे रहा है वह सफल नहीं हो पायेगा इसलिये मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी कड़ाई से और निर्भीकता से इस पर हमारा शिक्षा मंत्रालय कार्रवाई करेगा । धन्यवाद ।

(Interruptions)

SHRI K. MOHANAN: Sir, the scope is very limited. This is not a discussion on... *(Interruptions)*. This is a question on the strike of the University Teachers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please, sit down Mr. Mohanan.

***SHRI N. RAJANGAM** (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman Sir, Today, the whole country is viewing with serious concern the country-wide strike by two and half lakh College and University teachers. On the other hand as a result of this, about thirty to thirty five lakhs of students have fallen victims. The country is watching curiously, the steps being taken by the Government in this regard. I also feel that the Government should take some effective steps at the earliest possible time.

The Government of India is also aware that the Government of Tamil Nadu is the first state to accept the 80 per cent central assistance towards the implementation of the new scales. It has also agreed to contribute the remaining 20 per cent of the expenditure. I would like to remind that the Government of Tamil Nadu has also implemented the recommendations of the University Grants Commission.

In the present situation the Union Government wants to have a centralised selection of College and University teachers. I would like to ask the Government the practicability of such modality of selection. As the Colleges are affiliated to Universities, it is the duty of the University concerned to select teachers. So, it does not seem proper to have a centralised selection for it would pave way for many misgivings. This method of selection will, in the long run, neither benefit teachers nor keep the Government in a convenient position. There ought to be chaos. The future will decide and you will know it yourself.

Let us suppose that you send a Marathi speaking teacher to Tamil Nadu to teach a subject. Is it possible for him to teach the subject with all devotion? Will the students be pleased to learn from him? It is not possible because of the cultural difference. Since education is part of the cultural ethos of the society, there will be a communication gap in such a situation. I make this point or my observations as a teacher. By merely enacting a law you cannot bulldoze anything that you wish. I fully understand the situation. Silence of the Government is not the right approach when we view the magnitude of the problem. You should also see the consequences of this problem. If the students go on strike at the all India level, what would be the position of the Government? Since education is closely linked to cultural heritage of the society, people will not accept the delinking of one from the other. Education can prosper only if it remains linked to the culture of the people. So, I request you to view this matter with great caution.

Next, I wish to point out the problem of the multiplicity of scales. You have now provided three grades for Lecturers with three different scales. But the teaching community has some misapprehensions about it. So, I feel, the provision of grades and promotions should be left to the University authorities, who are the best judge. The habit of demanding more salary began only after independence. It is the Government which is responsible for this. Whenever it brings a change in the pay scales, there are anomalies and there are agitations. It is high time we put a full stop to this.

As regards the screening of teachers for promotions, it is said that there would be national level examination. Why can't it be at the state level? Do you apprehend some problem in it? I think the best method of screening them could be carried out at the State level. It should be left to States to decide on these modalities. There are many

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

[Shri N. Rajangam]

more problems in this aspect. For example there is a history teacher who studied history in the year 1940 like me. But he continues to teach history even today though there are new things that have filled the pages of history. Thre are incidents where the history is re-written. Then what he is going to teach? These are serious problems. There are controversies even in the so called Merit promotion scheme. What do you mean by merit? I am sure it would be in advantage of the elite group. Only those from the aristocratic and the fortunate society can get the best out of it. The worst affected lot would be the unfortunate down trodden who can never compete with the fortunate ones. Dr. Ambedkar has been pleading all along his life for special promotion avenues for the down trodden, the scheduled caste. I fear, the present scheme will go against his wish. The Government is yet to carry out the providing of special promotion avenues for the unfortuante ones.

Now I come to the issue of strike by the teaching community. These are the people who make Presidents, Governors, *Ministers and Scientists. So, it is not good* on their part to resort to the method of strike like students. The Government should also do something about it. Both should come to the negotiating table. I would like to remind that this method of negotiation has been suggested in the Tamil weekly known as 'Thaai'.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, Mr. Chimanbhai Mehta. I would request the Members to be brief.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, after hearing all the speeches here, I think that we can narrow down our differences and come to some sort of an understanding and I have high hope that Narasimha Raoji, for whom even the Opposition benches have great regard and respect, would be able to give some direction which will lead to solution of the strike.

At the outset, Sir, allow me to say that the strike by the college teachers is not a very welcome phenomenon because already we are facing student problems and the students would be getting encouragement and they themselves, at least a section of them, do not want that indiscipline should continue in the university campus. But the teachers have perhaps been compelled to go on strike. I do not want to moralise to them that it is wrong on the part to go on strike; of course, it is wrong. But when wise people do something wrong, all should sit and think about it and try to find out why they have done so. The speech by Ratnakarji was really a very illuminating speech. And, after hearing that, although he might have stretched certain things too far by saying that Professors are not prepared to mark the attendance registers, that they are not coming in time and several such things, I think there is one section of the society that has polluted the entire society. We, the politicians, are the first to be blamed for this kind of indiscipline. People say that teachers should not behave like this, like trade-unionists. I am a trade-unionist and I would request them to understand trade-unionism. It does not mean anarchy. Trade-unionism does not mean only strikes. I would say that the best trade-unionist that India has produced was Mahatma Gandhi. He is known as the National leader or the Father of the Nation. So, don't have a mean conception of the trade-union movement. Trade-union movement is basically meant for advancing democracy and protecting workers' rights. In the same way, the teachers have to think of raising the level of education, serving the society and also serving themselves. We should take all these ingredients into consideration.

I know that the opposition benches are also quite sensitive on all these points. They are not here to exploit the situation. There is a genuine desire on the part of all to come to some settlement. I have received a memorandum or a note from the teachers. There are 10 points. I think some of the points can be considered. The tenth point is that the principle of parity in 1973 has now been disrupted. The Class I *will* now get *Rs. 2400/-* more than the Lecturers at the 20th year of service. Why do we favour I.A.S. bureaucracy or the Central Services to this extent? Naturally

causes some discrepancies and heart-urning.

Then, there is the question of number grades. The claim is that there are ready 5 grades. Since the selection grade as abolished in 1973 and the Professors' nning grade is not in operation, the achers demand a running scale of Rs. 200/- to Rs. 7300/- on three-tier basis. he existing merit promotion scheme has en abolished for all new incumbents.

Promotion and evaluation. Why do you sist on national evaluation? Our States e also quite big as some countries in urope. I don't know why there is this sistence on national level merit and ational level eligibility for services. This n be sorted out. It is not that difficult. hese are the points.

About central assistance and this 80 per nt, I think these points are not that diffi-ilt. I think we can definitely sort them it. This should not be so difficult for Shri arasimha Rao who is a very eminent atesman of our country.

Now one thing disturbs me. The tea-ers say that they want to discuss with m, but no discussions took place. Let not sit on prestige: first call off the ike, then we will discuss. That was e approach of Shri Morarji Desai in e past and he created so many prob-ms.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Madhya Pradesh): Why bring Morarji esai here?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: He is t like that. I know him. He is a ry modest Minister who would like to scuss it with the teachers. An atmos-ere should be created for it. This is very circular thing. They call it cir-lar logic. You don't invite them for scussion because they have gone on ike. You did not call them for dis-ssion and they have gone on strike. Now ey are on strike and you ask them to ll off the strike to start discussions. , this is not the way to tackle the uation. I think, speakers from both sides have at least made a common point. And the common point which the Ministry would take into consideration is that a dialogue must be there because 34 lakh students are involved, the education system is involved. And there should not be any heart-burn among teachers because they are very important people. Of course, Ratnakarji is absolutely right that some of them are not working according to discipline. But I am not blaming them. I would blame myself also for all these things because we are giving very bad examples to our nation. And, therefore, let all of us go and start the dialogue. Thank you, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is really interesting to note that the policy being pursued by the Ministry of Education stands largely isolated or condemned in the House because while listening to the speeches of my friends on the other side, I had seen a sincere expression from their side asking the Minister concerned to sit in negotiation with the striking teachers. I wholeheartedly endorse the appeal made by Mrs. Heptullah to the Minister of Human Resource Development for immediate negotiations with the striking teachers. I unequivocally condemn the attitude that the Government has taken towards the striking teachers that the teachers must withdraw their strike, otherwise there cannot be any negotiation. If the Government can begin negotiations with the armed terrorists in Darjeeling district, what prevents them from entering into a negotiation with the striking teachers? If the Government could have negotiations with the armed rebels in Mizoram and restore peace in that part of the country, I do not know what prevents them from entering into a negotiation with the striking teachers. If the Government can advise the militants in Sri Lanka to enter into a negotiated settlement with the Government there in a situation when bombs are thrown on the floor of the Parliament of that country, as it happened today, I do not know what prevents the Government from entering into a negotiation with the striking teachers. Sir, I believe, this is the psychology of the priavte sector. Mr. Narasimha

[Shri Gurudas Das Gupta]

Rao has taken up the psychology of the private sector. I believe, Mr. Narasimha Rao has entered into or taken up a policy of total confrontation with the striking teachers numbering lakhs in our country. I would like the Minister to tell us what his intention is? Does he want to settle the dispute or does he want to break the strike? What is the objective or the perception or the psychology or the basis on which his policy towards this strike is actually calculated or built up? Does he want to break the strike or does he want to bring about a settlement? If it is a question of breaking the strike, then I should say, well done, gentleman, hats off to you for the way you are proceeding. If the attitude of the Government is to settle the dispute, I must say the step that you have taken is too dangerous for the country. Sir, may I remind you that it is Margaret Thatcher who had taken this line to break the coalminers strike in the Great Britain? I do not know whether the grand old gentleman has found something common with the grand old lady. If it is so, it cannot be a matter of pride for us. I believe, Sir, that the attitude of the Government has to change. The attitude has to change because there has been a universal appeal from all corners of the House for an immediate negotiation and an immediate settlement. I would like to tell my hon. Minister that he can break the strike, he can break the morale of the teachers, that he can disgrace the teaching community, but I would like to tell him, please remember, a disgrace to the teaching community cannot bring dignity to the nation. Therefore, the policy that you adopt must be judged in terms of the probable repercussions or the impact on the community or the nation as a whole. Therefore, I would like the strong-hearted gentleman presiding over the administration of Human Resources to give up his dehumanising attitude towards the problem that the country faces today.

I do not want to go into the demands of the teachers. That is a matter for the Commission to decide, that is a matter to be settled by the Government, that is a matter to be settled in the course of negotiations. But I appeal to the Minister to bring the issue from the street to the table or around a table, because it is this attitude which can solve the problem.

Lastly, Sir, the Government needs only Rs. 33 crores to take the full responsibility of the increased pay scales and that is nearly half of the kickback involved in the Bofors' deal. Why cannot the Government take that additional responsibility because it is a social investment? It is not a monopoly investment to be judged in terms of quick return. But the money that you are spending for education is a social investment. It will be judged in terms of the return, that is, to the extent we have built a healthy future for our own country. Therefore, Sir, along with my great colleague Mrs. Heptulla, I appeal to the Minister of Education to immediately begin negotiations and not to refrain from taking up the responsibility on his shoulders of spending nearly half of the kickback for building up a health India and a healthy future. Thank you.

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष जी, यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है कि करीब सवा दो लाख विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों के शिक्षक आज हड़ताल पर हैं। पन्द्रह दिन से हड़ताल चल रही है और छात्रों का कितना नुकसान हुआ है इसकी कल्पना की जा सकती है। हमारे एक साथी इधर से बोल रहे थे और वह कह रहे थे कि शिक्षकों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि सभी यही सोचेंगे, जो राइट टू किंग पीपल हैं, कि जहां तक हो शिक्षकों की हड़ताल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन का ही नहीं छात्रों का भविष्य जो है, वह अधर में लटक जाता है, छात्रों का नुकसान होता है और यह भी सही है कि कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में - मैं तो यहां सात-आठ साल से हूं जब से एम०पी० हूं, मैं देखता हूं कि हर साल हड़ताल होती है, कोई न कोई कारण हो जाता है और हड़ताल होती है और विशेष कर परीक्षाओं के समय हड़ताल होती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं, हालांकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं, लेकिन मैं चहता हूं कि छात्रों को ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपनी हड़ताल चलायें और जहां तक परीक्षायें हैं, उस समय तो उन्हें हड़ताल करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि होती है और अगर शिक्षकों से बात कीजिए तो वह कहेंगे कि अगर हमारी न्यायोचित मांग नहीं मानी जाती, तो हम क्या करें? हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? तो एक कलेक्टिव बारगेनिंग का जो सिद्धांत है, वह अपनाया जाता है और इस समय जो हड़ताल चल रही है, इसमें तो हमको यह लगता है कि शायद ठीक नहीं हो पाई, वार्ता के अभाव में ही हड़ताल चल रही है क्योंकि नरसिंह राव जी के समय में चल रही है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हमें थोड़ा आश्चर्य है क्योंकि आप प्रशासन में बहुत ही दक्ष हैं और मुझे मालूम है कि जब आप मुख्य मंत्री थे तो शायद एक बार ही इनके कर्मचारियों ने हड़ताल की हो, हड़ताल की नौबत नहीं आने वाली। उनकी मांग है। उनकी न्यायोचित मांगें यह मान लेते थे। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो गए थे कर्मचारियों को भड़काने के लिए।

श्री पशपति नाथ मुकुल : हां, मैं गया था। मैं गया था और यह अध्यापकों की हड़ताल का सिलसिला बहुत बाद में शुरू हुआ, पहले कर्मचारी ही हड़ताल किया करते थे। हमें मालूम है, उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की पहली हड़ताल 1968 में हुई, मैं उस समय कर्मचारी फेडरेशन वर्ग का अध्यक्ष था। हमारी हड़ताल 1966 में हुई थी। लेकिन उस समय भी हम शिक्षकों से कहते थे तो वे कहते थे कि हम कैसे हड़ताल करें, हम तो शिक्षक हैं। लेकिन वही शिक्षकों ने दो साल बाद 1968 में हड़ताल की। एक स्थिति आ जाती है जब आप नैगोशिएट करते-करते, करते-करते समझते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी और हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। जो वर्कर्ज हैं, जो वेज अर्नर हैं टीचर भी वेज अर्नर है, आज पी०सी०एस० अफिसर्ज हड़ताल कर चुके हैं, जुडीशियल आफिसर्ज हड़ताल कर चुके हैं, डाक्टर्ज एंड इंजीनियर्ज हड़ताल कर चुके हैं जो कि बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि आज के समय में टीचर हड़ताल नहीं करेगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वह हड़ताल न करने पाए, हम ऐसी परिस्थितियां बनाएं कि आ करके बात हो जाए और मामला रफा-दफा हो जाए। न पूरी उनकी रही और न पूरी हमारी रही, बीच में नैगोशियेटिव सैटलमेंट हो जाए। लेकिन यहां इस प्रकार की वार्ता का अभाव है। मैं तो समझता हूं कि आज देश भर के विश्वविद्यालयों के शिक्षक और डिग्री कालेजों के शिक्षक आज हमारी सरकार के बड़े ऋणी हैं पहली बार यह एकता उसमें बनी है और यह एकता हमारी सरकार ने बनवाई है। पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों के टीचर्ज की हड़ताल हो रही है और इसको कराने का श्रेय हमारी सरकार को है। अब देखना यह है कि हड़ताल कितनी जल्दी खत्म होती है? जैसा उनकी मांगों के बारे में तमाम चर्चा हो चुकी है। 1983 में आपने उनको पर्सनल प्रोमोशन स्कीम दी, मैरिट प्रोमोशन स्कीम 1983 में दी और चार वर्ष बाद आप उनसे छीन रहे हैं। कोई भी चीज किसी को दे दी जाती है तो वह विदड्रा नहीं की जाती। मुझे मालूम है 1983 में भी जब यह स्कीम उनको दी गई थी तो हड़ताल चल रही थी और मिसेज गांधी के कहने पर यह समझौता सरकार ने किया था और यह घोषणाएं की थीं। वरना शायद हड़ताल और चलती। लेकिन मिसेज गांधी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर मिनिस्ट्री को एक तरह से आदेश दिया था कि नहीं, कल यह समझौता हो जाना चाहिए और समझौता हुआ। तमाम बनिफिट्स, तमाम चीजें उनको दी गई थीं और आज आप उनको वापस ले रहे हैं। जब वापस लेंगे तो यह निश्चित है कि शिक्षक हो या छात्र हो, कर्मचारी हो या नेता हो, वह जरूर लड़ेगा और संघर्ष करेगा तथा मांग करेगा। आज आप एक वेतनमान के तीन वेतनमान कर रहे हैं। लैक्चरर के तीन, प्रोफेसर के तीन। लैक्चरर के तीन वेतनमान आप क्यों कर रहे हैं? एक वेतनमान से काम चल रहा था, सिलैक्शन गेड बीच में आपने लगा दिया था, लेकिन वह भी मैं समझता हूं कि बाद में खत्म हो गया था। तीन वेतनमान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको प्रोमोशन नहीं दे पाते। आप उनको आभास दिला रहे हैं

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

कि नहीं, मेरा वेतनमान बढ़ गया और रहे लैक्चरार के लैक्चरार ही । लेकिन एक वेतनमान के तीन वेतनमानों में स्पलिट करके आप केवल उनका मनोवैज्ञानिक रूप से इलाज करना चाहते हैं, जबकि वे शिक्षक हैं, बड़े समझदार हैं, वे जानते हैं और वे समझते हैं इस चीज को कि यह तो एक साइकोलोजीकल चीज है और इसमें हमको मिलना कुछ नहीं है । हम लेक्चरार के लैक्चरार ही रह जायेंगे । 80 परसेंट लैक्चरर्ज बिल रिटायर एज लैक्चरर्ज क्योंकि पर्सनल प्रोमोशन स्कीम आपने उनको दी थी और आप उसको भी विदड्रा कर रहे हैं । उसमें कम से कम यह था कि पोस्ट नहीं क्रिएट होती थी, उनका वेतन तो बढ़ जाता था । प्रोफेसर का वेतन वह पाने लगता था, रीडर का वेतन पाने लगता था । एक तरह की पर्सनल पे वह होती थी और समय आने पर तने वर्ष बाद वह उसे मिल गया । आज आप वह पर्सनल बैनिफिट उनसे छीन रहे हैं और आप चाहते हैं कि वे हल्ला भी नहीं मचाएं, कहें भी नहीं । ये दोनों बातें नहीं चलेंगी । जो नए वेतनमान आये हैं उनमें मैंने देखा है कि आपने प्रोफेसर आफ एमीनेंस को तनख्वाह आठ हजार पर फिक्स कर दी है लेकिन वाइस चांसलर का जो स्केल है वह 7600 है । तो प्रोफेसर आफ एमीनेंस वाइस चांसलर से ज्यादा तनख्वाह पायेगा । क्यों पाएगा, मेरी समझ में नहीं आता ? इसमें तुक क्या है ? वाइस चांसलर तो उसमें सीनियर ही हुआ यह कंट्राडिक्शन कैसे पैदा हो गया ? यह सीनियर जूनियर का कम से कम पैसे के मामले में तो माना ही जायगा । . . . (व्यवधान) . . . प्रोफेसर जो होंगे उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और वाइस चांसलर का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा ।

6 P.M.

तो इसलिए मैं अधिक कुछ न कहकर, काफी लोग इसमें कह चुके हैं, यही माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जैसा हमारे और साथियों ने कहा है वे जल्दी से जल्दी इसको सुलझाने की कृपा करें, वे इस योग्य हैं, उनमें सामर्थ्य है, उनमें इतनी दूरदर्शिता है कि वे कर सकते हैं । साथ ही मैं शिक्षकों से भी अपील करूंगा कि हड़ताल को लंबा मत कीजिए क्योंकि हड़ताल ज्यादा लंबी खींचने पर ही उसके प्राण निकल जाते हैं और अभी तो तनख्वाह मिल चुकी है, 4 अगस्त से हड़ताल हुई है । अगर महीना, दो महीना चली तो हड़ताल टूटेगी, फ्रस्टेशन पैदा होगा । तो मेरी दोनों दलों से यह अपील है कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं, हड़ताल को लंबा न खींचें और बैठकर के हमारी सरकार के साथ, शिक्षकों के जो नेतागण हैं, रास्ता निकालकर जल्दी से जल्दी इस हड़ताल को खतम करें । यही अपील मैं दोनों पक्षों से करना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं इस पर बहुत विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेहरोत्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से 40 साल के जो टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं, उनके अधिकारों पर हमला हुआ है । यहां जो अधिकार उन्होंने 40 साल से लड़कर लिए थे, उन अधिकारों के छिनने का उन्हें अहसास हुआ है । इसमें जितनी भी सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों के चलते आगे भी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनके साथ भी उनका झगड़ा होगा और उनकी हड़तालें चलेंगी । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दोनों सदन की राय और मेरी भी राय उनके बारे में बहुत आदर की है, 17 तारीख को जब शिक्षक लोग और उनके अगुवा लोग; आपसे बात करने के लिए गए तो 17 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में जो वक्त आपके पास में था, आप उनसे बात कर सकते थे, लेकिन आपने इतने लंबे समय तक बात नहीं की और उस समय के बीच जब हड़ताल नहीं हुई थी, 4 अगस्त से हड़ताल पर जाने की बात की, तो उस बीच में आपको बात करनी चाहिए थी । चूंकि अब कह रहे हैं, हड़ताल हो गयी है, हड़ताल वापस लो तभी बात करेंगे जब हड़ताल नहीं हुई थी, वे आपके पास गए थे, आपसे बाकायदा उन्होंने निवेदन किया था कि हम पैसे के मामले पर आपसे नहीं लड़ना चाहते यह जो संघर्ष

है या लड़ाई है या मान की, प्रतिष्ठा की, मर्यादा की है, इसमें सरकार का पैसा जाने वाला नहीं है तब आपको बात करनी चाहिए थी।

अभी माननीय रत्नाकर जी का भाषण मैं सुन रहा था। वह जिस अंदाज में बोल रहे थे, समस्त उनका मानस ऐसा था कि वह धमका रहे थे कि इनकी कोई बात न मानी जाय। हड़ताल का जहां तक है, पूरे देश के जितने शिक्षक हैं, इस मेहरोत्रा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं और मेरे ख्याल से सभी पार्टियों से संबंधित लोग इसमें हैं, पूरे लोग चले गए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी बात मान लीजिए, आप उनके लिए कोड आफ कण्डक्ट बना रहे हैं, लेकिन जो लोकतंत्र की मर्यादा है, लोकतंत्र का मान-सिद्धांत है, उनके अंतर्गत उनसे बात करने से आप लगातार मना कर रहे हैं, और आपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बाकायदा एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि आगे यह हड़ताल और ज्यादा गंभीर रूप धारण करेगी, 19 तारीख को उनका विशाल प्रदर्शन है, इसके बाद वे सत्याग्रह पर जाएंगे और जेल जाने का काम भी करेंगे। यह काम वह इसलिए कर रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अकेले शिक्षक नहीं रहेंगे, अभी तक हम लोग इस हड़ताल को चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में एक बढ़िया वातावरण में बात हो जाय और आपके और उनके बीच जो गलतफहमी है, वह दूर होने का काम हो क्योंकि इसमें पैसा और वित्तीय मामला नहीं है।

लेकिन यदि आपने बात करने का सिलसिला नहीं चलाया और यह मामला आगे बढ़ा तो मैं जानता हूं कि विद्यार्थी भी इसमें बड़े पैमाने पर शरीक होंगे। एक जो तनाव नहीं बनना चाहिए वह तनाव पैदा होगा और उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए मैं मंत्रीजी से पुनः अपील करता हूं कि वे उनको वार्ता के लिए बुलाएं। हो सकता है कि मंत्रीजी की बात से वे कनविंस हो जाएं, लेकिन उनसे बात करने का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए और सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया तो स हड़ताल के बारे में हमारा जो मानस है कि उनकी मांगे न्यायोचित हैं, उसे हम भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे। इससे मामला बिगड़ेगा और तनावमय होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा० एम० हाशिम किदवई (उत्तर प्रदेश): जनाब वाइस चैयरमेन साहब और दोस्तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमारे नौजवान और अबल अजम प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी और हमारे लायक मिनिस्टर नरसिंह राव जी ने हमारे मुल्क में नयी एजुकेशन पालिसी शुरू की जिस वक्त इस पालिसी का ऐलान किया गया इसके मकसद से बेइन्तहा खुशी हुई। इसको देखकर यह शेर याद आ गया,

"उठ के अब बज्मे जहां का
अंदाज है, मशरिक ओ मगरिब में
का आगाज है।"

हम सबको बड़ी खुशी हुई तालीम के मैदान में हमारा मुल्क बहुत तालीमी ढांचे में जबरदस्त तबदीलियां लेगी और अंग्रेजी की बनाई हुई पालिसी की खामी दूर हो जाएंगी। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त मुल्क में एक ऐसा वाकिया हुआ है जो बहुत ही अफसोसनाक है अपने मुल्क के बड़े कालेजों और यूनिवर्सिटीयों के टीचर्स स्ट्रायक पर हैं जिनका काम हमारी नौजवान नस्ल को तालीम देना है और उनको तरबीयत देना है। बदकिस्मती से आज वे स्ट्रायक पर हैं। क्योंकि इस मसले पर हमारे बहुत-से दोस्त अपने ख्यालात का इजहार कर चके हैं इसलिए मैं सिर्फ दो-तीन उसूली बातें मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि उनके जैसे लायक मिनिस्टर की मदद से यह मसला जल्द-से-जल्द हल हो जाय। उनका एक मसला तो यह है कि बजाय 3 ग्रेड के अब 7 ग्रेड हो गए हैं। हम सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं नहीं समझता कि 3 के बजाय 7 ग्रेड करने से कैसे हम सोशलिज्म की तरफ चलेंगे। लिहाजा जितनी जल्दी हम ग्रेडस को कम करें उतना ही ज्यादा

[डा० एम० हाशिम किदवई]

अच्छा रहेगा। मैं बड़े अदब के साथ मिनिस्टर साहब से फिर यह दरखास्त करूंगा कि इस मसले पर वह गौर फरमाएं और जल्द-से-जल्द इस मसले को तय करा दें। यह मसला ऐसा नहीं है जिसमें कि गवर्नमेंट बजा प्रिस्टिज को दखल दें। पार्लियामेंट के वे मेम्बर जो टीचर रह चुके हैं और टीचर हैं इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं इस बारे में अपनी भी नाचीज खिदमात पेश करता हूं ताकि इस मसले को जल्द-से जल्द हल किया जा सके ताकि हमारे 34 लाख नौजवान जो यूनिवर्सिटियों और कालेजों में पढ़ रहे हैं जिन्हें कि मुल्क में बड़े-बड़े काम करना है वे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। और उनका कीमती वक्त जाया न हो। इस वजह से स्ट्रायक की और लम्बी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दूसरा मसला है कि प्रमोशन स्कीम वापिस ले ली गयी है, यह भी नहीं होना चाहिए। बल्कि इसे बरकरार रहना चाहिए। मैं एक बात और बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि नयी एजुकेशन पालिसी में टीचर्स में, आई०एस०एम० में पैरिटी लानी चाहिए। हमारे मुल्क में टीचर्स का बड़ा दर्जा रहा है। दूसरी तरफ गुरू सेवा हमारे मुल्क की तहजीब का खास पहलू रही है इसके यानि टीचर की इज्जत और विकार का भी बहाल होना चाहिए कोई वजह नहीं है कि इसे हम बरकरार न रख सकें। लिहाजा मैं बडे अदब के साथ मिनिस्टर साहब से दरखवास्त करूंगा कि वे जल्द-से-जल्द इस मसले को हल करें ताकि स्ट्रायक खत्म हो और हमारे कालेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम शुरू हो। और तुलबा का वक्त जाया न हो और नई तालीमी पालिसी पर अमल दर आमद हो इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि तालीमी इदारों में खास कर यूनिवर्सिटियों में एकेडिमिक तालीमी जमूहरियत कायम हो।

†[ڈاکٹر ایم - ھاشم قدوائی (اتر پردیش): جناب وائس چیرمین صاحب اور دوستوں - ھماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ ھمارے نوجوان اور ابولعزم پرائم منسٹر شری راجیو گاندھی اور ھمارے لائق منسٹر نرسمہا راؤ جی نے ملک میں نئی ایجوکیشن پالیسی شروع کی - اور جس وقت اس پالیسی کا اعلان کیا گیا تو اس کے مقصد سے بے اندھا خوشی ھوئی - اور اسکو دیکھ کر یہ شعر یاد آ گیا -

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ھی انداز ھے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ھے

ھم سب کو بڑی خوشی ھوئی کہ تعلیم کے میدان میں ھمارا ملک بہت آگے ھوگا - اور تعلیمی ڈھانچے میں زبردست تبدیلیاں ھوں گی اور انگریزوں کی بنائی ھوئی پالیسی کی خامیاں دور ھو جائیں گی لیکن ھماری بڑی بد قسمتی ھے کہ اس وقت ملک میں ایک ایسا واقعہ ھوا ھے جو بہت ھی افسوسناک ھے- یعنی ملک بھر کے کالجوں اور یونیورسٹی کے تیچرس اسٹرائک پر ھیں جن کا کام ھماری نوجوان نسل کو تعلیم دینا ھے- اور ان کو تربیت دینا ھے بد قسمتی سے آج وہ اسٹرائک پر ھیں - کیونکہ اس مسئلے پر ھمارے بہت سے دوست اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ھیں - اس لئے میں صرف دو تین اصولی باتیں منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاھونگا اور یہ چاھونگا کہ ان کے جیسے لائق منسٹر کی مدد سے یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ھو جائے - ان کا ایک مسئلہ تو یہ ھے کہ بجائے تین گریڈ کے اب سات گریڈ ھو گئے ھیں - ھم سوشلزم کی طرف بڑھ رھے ھیں اور میں نہیں سمجھتا کہ تین کے بجائے

†[ ] Transliteration in Arabic script.

سات گریڈ کرنے سے کیسے ہم سوشلزم کی طرف چلیں گے - لہذا جتنی جلدی ہم گریڈس کو کم کریں اتنا ہی اچھا رہے گا - میں بڑے ادب کے ساتھ منسٹر صاحب سے پھر یہ درخواست کرونگا کہ اس مسئلے پر وہ غور فرمائیں اور جلد سے جلد اس مسئلے کو طے کرا دیں - یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے- جسمیں کہ گورنمنٹ بےجا پریشر کو دخل دے - پارلیمنٹ کے وہ ممبر جو ٹیچر رہ چکے ہیں اور ٹیچر ہیں اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں - اس بارے میں اپنی ہر ناچیز خدمات پیش کرتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جا سکے - تاکہ ہمارے ۲۴ لاکھ نوجوان جو یونیورسٹیز اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں جنہیں آگے چلکر ملک میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں وہ اپنی پڑھائی شروع کر سکیں - اور ان کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اسوجہ سے اسٹرائیک کی اور بھی گنجائش نہیں رہنی چاہئے - اور دوسرا مسئلہ ہے کہ پرموشن اسکیم واپس لے لی گئی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہئے - بلکہ اسے برقرار رہنا چاہئے میں ایک بات اور بڑے ادب سے عرض کرونگا کہ نئی ایجوکیشن پالیسی میں ٹیچرس میں آئی - اے - ایس - میں پیوٹی لانی چاہئے ہمارے ملک میں ٹیچرس کا بڑا درجہ رہا ہے- دوسری طرف ڈگری سیولائز ہمارے ملک کی تہذیب کا خاص پہلو رہی ہے - اس کو یعنی ٹیچروں کی عزت اور وقار کو بحال ہونا چاہئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے ہم برقرار نہ رکھ سکیں - لہذا

میں بڑے ادب کے ساتھ منسٹر صاحب سے درخواست کرونگا کہ وہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کریں تاکہ اسٹرائک ختم ہو اور ہماری کالجوں اور یونیورسٹیز میں تعلیم شروع ہو - اور طلبہ کا وقت ضائع نہ ہو اور نئی تعلیمی پالیسی پر عمل در آمد ہو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی اداروں میں خاص کر یونیورسیٹیوں میں اکیڈیمک تعلیمی جمہوریت تاکہ ہو -]

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is very sad that nearly 2,30,000 teachers from 5,600 colleges and 150 universities are on strike today since 4th August. Those who shoulder the responsibility—a stupendous task—of moulding the future generation are on strike. I am surprised, rather shocked, at the attitude of obduracy and intransigence of the Education Ministry. They have closed all the doors.

The teachers have taken all possible steps to ventilate their grievances, to put forth their demands, since 1986. On 6th November 1986, march to Parliament; 4th December, courted arrest; 6th February, hunger strike before UGC office; 11th February, demonstration before UGC office; 25th February, went on a token strike throughout India; 9th March, demonstrations in all State capitals. On 24th March they gave a strike notice. Even then our honourable Minister did not meet them.

Sir, I do not understand why the three grades have been increased to six. The Radhakrishnan Commission opposed it; the Kothari Commission objected and opposed the multiplicity of grades and hierarchic structure; the Sen Committee also had opposed it. For what reasons? What are you going to gain through it?

One of the main grievances of the striking teachers—which seems most reason-

[Shri V. Gopalsamy]

able to me—is that statutory bodies of the universities such as the Academic Council and executive Council which were duly empowered to decide service conditions, appointments, probation and promotions, due to the Ministry's notification, were reduced, virtually, to the status of rubber stamps.

Sir, here the lecturers are the most affected category under the new scheme. New recruits to the profession will take a minimum of 20 years to attain selection grade. Earlier it was possible in 10 or 15 years. Those in the 9th and 14th year of service will be fixed in the scale of Senior Lecturers. They have to wait for 12 more years for the selection grade which, under the Merit Promotion Scheme, would have been available to them in a year's time.

Sir, I would like to request the honourable Minister: Why don't you consider the suggestion of pay fixation to be made notional? Prof. Lakshmanna also put forth that demand. He could consider that.

Some of the recommendations made by the Mehrotra Committee have not been accepted regarding provision of Rs. 1,000 per annum as professional allowance. Something more could have been offered. You could make it Rs. 2,000 or Rs. 3,000. When you expect them to equip themselves, why don't you provide a professional allowance? And the Merit Promotion Scheme should continue. In the Merit Promotion Scheme also there is evaluation.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I am really very sorry about the present attitude of our honourable Education Minister, Mr. Narasimha Rao, for whom I have the greatest respect. He is a great scholar, a versatile genius with a compassionate attitude. Why has he, all of a sudden, turned a rigid man? He has been flexible. But he has become very rigid.

Also, Sir, he should forgive me if I put it like this because I have got respect for him. There is a feeling that now-a-days he has become a strike-breaker because it is to his credit that he has broken the junior doctors strike and the teachers strike, and he wants to attain a hat-trick by breaking this strike also. This sort of notion should not be created. The door has been closed. Mr. Education Minister, now the ball is in your court. Sit together across the table. When they demand something, three demands or four damands are there, if you sit together and talk to them, give-and-take could solve it. Otherwise, if you do not break the impasse, if it continues, then, thousands of teachers will be going to jails. The student community has also been very much affected. The campus unrest has become the biggest problem of this country. Therefore, Sir, such an impression that our hon. Minister, Mr. Narasimha Rao now-a-days has become a strike-breaker, that impression should not be there.

Also, Sir, one more thing. For what reasons has the bureaucracy taken up the cudgels and launched a campaign against this strike of the university teachers?

Therefore, Sir, I would like to appeal to our hon. Education Minister. Let Rajya Sabha get the privilege of getting an announcement from him to end the strike.

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मुझे भी आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बात सच है कि आज जो सदन में चर्चा का विषय है वह मानव विकास मंत्री जी की वजह से आया है। आज से 4 दिन पहले प्रश्न काल में एक सवाल था उसमें बार-बार इन्होंने कहा था कि यह समस्या बड़ी लम्बी और उलझी हुई है इसलिए इस प्रश्न काल में विस्तार से नहीं बता सकता बल्कि सदन में इस पर विवाद मांगा जाये। यह विवाद उनकी तरफ से आया है इस के लिए बधाई के पात्र हैं। आडवाणी जी और अन्य सदस्यों ने भी कहा कि इसमें कोई आर्थिक मामला ज्यादा नहीं है। यह सारे सदन का इधर-उधर से रूख है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हड़ताल अच्छी है या खराब

है मैं हड़ताल के हक में कभी नहीं रहा। जैसा कालदाते जी कह रहे थे हम भी हड़ताल तुड़वाने वालों में रहे चलाने वालों में कभी नहीं रहे जीवन भर। जब भी कभी हड़ताल कोई करता, गैंदा जी हो या झारखंड की हड़ताल रही हो हैं हमे जूस का गिलास लेकर उनकी गरदन पकड़ कर तब करता था इतना अधिकार में समझता था हड़ताल तुड़वाने के लिए। जापान का उदाहरण हमारे सामने अनुकरणीय है। मैं स्वयं वहां गया हूं। मैंने देखा है कि वहां के लोग जब भी हड़ताल करते हैं या गुस्सा दिखाते है तो काली पट्टी बांधते हैं काम बंद नही करते। वह धन्यवाद के पात्र हैं वह बधाई के पात्र हैं। मैं वहां की सरकार को भी बधाई का पात्र मानता हूं जो काली पटटी बांधने मात्र से ही यह समझ जाती है कि लोग नाखुश हैं, नाराज हैं। उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। यह नहीं है कि वे काली पटटी बांधें रहेंगे बहुत दिनों तक या उनकी बातों को नहीं सुना जायेगा। वे दोनों बधाई के पात्र हैं। यही वजह है कि सारी दुनिया में एटम बम गिरने के बाद भी जापान बड़े बड़े देशों को सामान दे रहा हैं, सामग्री दे रहा हैं। आज हमारे देश को उसका अनुसरण करना चाहिए अगर जापान की तरह अपने देश को उठाना है तो।

इस हड़ताल पर तो सुकुल जी भी आश्चर्य कर गये। कभी-कभी लीडर जो होते हैं वह भी लोगों को उकसा कर हड़ताल करवा देते हैं। सुकुल जी माँफ करेंगे में सही बात कह देता हूं। कभी-कभी हड़ताल में हमारी लीडरशिप भी निहित होती है अकारण। मैं एक ही बात आप से कहना चाहता हूं अध्यापकों के सम्बन्ध में कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी अध्यापक हुए हैं। राधाकृष्णन जी का जन्म दिन भी अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमारे देश में एक पुरानी परम्परा रही है। नाजमा जी ने भी पुराने आचार्यों, द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात से अपना भाषण शुरू किया। आज हमें पुरानी परम्परा की याद आ गई। आप जापान का उदाहरण ले लीजिये, चाहे अन्य देशों का उदाहरण ले लीजिये। मुझे अध्यापकों के पदाधिकारी मिले हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। मैं उन सारी बातों को यहां नहीं कहना चाहता हूं, मगर उनकी बातचीत का निचोड़ यही है और सदन में जो चर्चा हुई है, उसका भी निचोड़ यही है कि इस हड़ताल को समाप्त किया जाय। अध्यापक भी मूड में हैं कि हड़ताल समाप्त हो। हमारे श्री पी० वी० नरसिंह राव जी जब विदेश मंत्री थे तो कहा करते थे कि बातचीत से समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये और यही उपदेश ये हमें भी देते थे। लेकिन आज यह हड़ताल हो रही है तो वे बातचीत के जरिये इसको क्यों हल नहीं करते हैं? मैं तो अपने को उनके परिवार का सदस्य मानता हूं और उनके प्रति बहुत सम्मान भी रखता हूं, जब सारी दुनिया से आप बातचीत करके समाधान निकालने की बात करते थे, तो इस समस्या को भी बातचीत से हल कीजिये। आप अध्यापकों से बातचीत क्यों नहीं करते हैं। वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप आडवाणी जी से बातचीत कर सकते हैं, प्रो० लक्ष्मन्ना से बात कर सकते हैं, नाजमा जी० को आप बातचीत करने के लिये बाहर ले गये, तो इन लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? आज देश की हालत को देखते हुए, अध्यापकों की हालत को देखते हुए और इस सदन के मूड को देखते हुए आप उन लोगों से बातचीत कीजिये। उनको कल ही यहां पर बुलाइये। मैं उनको लाने की जिम्मदारी लेता हूं, सारे सदन की जिम्मदारी लेता है। इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं है और न ही इस मामले में पोलिटिक्स आना चाहिये। यह राष्ट्रीय प्रश्न है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सारा सदन प्रार्थना करता है, हम आपको इस बात के लिये बधाई दे हैं कि आप यह चर्चा यहां पर उठाई। इस चर्चा को यहां पर उठाने का श्रेय आपको ही है और इसके समाधान का श्रेय भी आप ही लीजिये। बच्चों के माता-पिता भी दुखी हैं, क्योंकि वे देखते हैं, उनके बच्चे कालेज नहीं जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करता हूं और

[श्री रामचन्द्र विकल]

आशा करता हूं कि आप इस समस्या का हल शीघ्र निकालेंगे और अध्यापकों से बातचीत करेंगे।

श्री धर्मचन्द प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो समस्या है, वह बहुत गम्भीर समस्या है। दो लाख के ऊपर अध्यापकगण हड़ताल पर हैं। इसका असर जैसा कि कहा गया है, लाखों विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, उनके माता-पिताओं पर पड़ रहा है, जो अपने बच्चों को घर पर बैठा देखते हैं। यह हड़ताल जो चल रही है, इस के बारे में अध्यापकों ने हमें बताया कि यह बड़ी मजबूरी में उन्होंने की हैं और यह समझ कर की है कि इसका परिणाम क्या होगा? इस समस्या का हल भी हो सकता है। इसमें दो धड़े हैं। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ अध्यापक हैं। अगर वे खुद कुछ नीचे उतरें और कुछ आप नीचे उतरें और आपस में मीटिंग करें, तो इस समस्या का हल निकल सकता है। अगर दोनों पक्ष जिद पर अड़े रहेंगे, तो समस्या और भी गम्भीर होगी। इससे विद्यार्थियों का जीवन और खराब होगा। अगर यह समस्या शीघ्र हल न हो सकी, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इससे खास कर जो साइंस के स्टुडेन्टस हैं, आर्टस के जो स्टुडेन्टस हैं, वह इतिहास को कवर कर लेंगे, भूगोल को कर लेंगे, लेकिन जो साइंस और मैडिकल के स्टुडेन्टस हैं, उनके लिये बहुत कठिन होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ उनको एक्सपैरीमेन्टस भी करने पड़ते हैं। वे इसको इतने कम समय में कैसा पूरा कर सकें, इस बात की ओर भी आप ध्यान दें। इन बातों को देखते हुए मैं नरसिंह राव जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस समस्या को वे शीघ्रातिशीघ्र सुलझायें। आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी, ऐसा मेरा विचार है। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति और आपका आदर भी है। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए, टीचर्स की डिमांड आपके लिये परेशानी का कारण हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी भी आपके सामने हैं और उनका भविष्य आपके सामने है। टीचर्स जो हैं, वे वही लोग हैं, जो देश के भविष्य के नागरिकों को बनाते हैं। आपको उनको देखना है। आप उनके पे-स्केल को देखें। आप सोचें कि समाज में आज एक टीचर का क्या दर्जा है? उनका दर्जा घटा है। जो दर्जा उन्हें पहले हासिल था, वह दर्जा नहीं है। मैंने 10-12 स्टुडेन्टस से इक्कठे पूछा, वे छोटे-छोटे स्टुडेन्टस थे कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो किसी ने कहा कि मैं डाक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने इंजीनियर और किसी ने पायलेट बनने की बात कही। लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि मैं टीचर बनूंगा। जब मैंने पूछा कि क्या टीचर बनोगे, तो उन्होंने सिर हिला दिया कि हम टीचर नहीं बनेंगे। यह बताता है कि टीचर का समाज में दर्जा बहुत गिर गया है। इस दर्जे को गिराने वाला कौन है। इसके लिये केवल टीचर ही दोषी नहीं है, बल्कि इसमें सरकार भी दोषी है, सरकार भी इसके लिये जिम्मेदार है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इस समस्या को सुलझाइये। आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। यह अगर अविलम्ब नहीं होता तो इसमें विद्यार्थियों के रास्ते में बाधा आयेगी, उनकी शिक्षा में बाधा आयेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सको सुलझायें। यह कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कुछ आप छोड़ें, कुछ वे छोड़ें। कहीं न कहीं मीटिंग प्वाइंट आ ही जायेगा।

SHRI K. MOHANAN: Usually the House is sitting upto 6 O' Clock. It is 6.25 now. We would like to know from the Minister for Parliamentary Affairs as well as from the Chair how much time it will take to finish this short duration discussion. (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Let him reply. We have sat so long.

SHRI K. MOHANAN: Let him reply tomorrow or day-after-tomorrow. Under extraordinary circumstances only we can sit late.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: No, for the next three days I am not going to be here. I wanted it to be concluded today. (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: We have been waiting for his reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I think the House has heard some unfortunate speeches today. Some of the speeches have been made to accuse the teaching community for going on strike. Without mentioning the hon. Member who has made this statement, I want to refute because, according to me, and I think the House will agree with me, this strike has been forced upon the teaching community. This is the reality. This is the fact. It is not of their own making. This strike, if I am allowed to say and I must say, is the making of the policy of yours, policy of the Government, which refuses to listen to the language of reason. Now, I want to remind the hon. House of a statement made by the hon. Minister of Human Resource Development, which he was pleased to make in the other House. I quote. He said,".. Teachers have nothing to lose but everything to gain if the strike is unilaterally withdrawn." I have not much time to dwell on this in detail. If the teachers today after listening to the advice of Mr Narasimha Rao withdraw the strike, what is the gain they are going to get? According to me, and I hope the House will agree with me, a unilateral withdrawal of the strike will force the teaching community to accept, to agree to accept, the following, namely, multiple grades, rejection of parity with Class I officers; they will have to agree to accept disparities in salaries in different States; they will have to agree to accept denial of promotion avenues; they will also have to accept the policy of erosion of autonomy in the universities; they will have to submit to hierarchisation and bureaucratisation. This is how the honourable Minister says the teachers will gain everything and lose nohting if the teachers unilaterally withdraw the strike. I had the misfortune of listening to another speech in this House which says that the universities and colleges should be brought under the purview of ESMA. There was a direct hint in it; I know. University campuses, colleges, are temples, are mosques, are churches? they are places of worship, places of learning; the campus should enjoy peace, etc. We are not interested in creating disturbances in the campus nor are we interested in vitiating the academic atmosphere in any academic institution of our country, although I am not a teacher, I am engaged in other ways. (*Time-bell rings*) I would only like to draw your attention that the Government has negated the concept of uniformity of pay-scales. I would like to quote the Government notification in this respect. The notification states—

> "The State Government, after takin the local conditions into consideration may also decide under its discretion t introduce scales of pay different fron those mentioned in the Scheme an may give effect to the revised scales o pay from January 1, 1986 or later."

My last point is this. What is th reaction of the State Governments? A far as I know, I am subject to correctior the Education Minister of Assam, Sikkim Tripura, Kerala, Karnataka and West Bengal have already stated that they woul not be able to implement the Schem without hundred per cent grant. This the reaction of a number of States. Wh about the reaction of other academ councils? The academic councils of t Central University of Hyderabad, tl Central Institute of English and Forei Languages, Hyderabad, JNU, AM Jamia-Milia and Delhi University ha decided not to endorse the notification 17th June. Allahabad University Sen and Utkal University Senate have supp ted the demands of the teachers. Th who is going to support you? Ratnaka Some bureaucrats? Who is going to st port you when the entire country, t student community, the teaching comm nity and also the House, almost una

[Shri Chitta Basu]

mously feel that a situation should be created in which the teaching community withdraws the strike? Mr. Honourable Minister, it is your responsibility to create a condition in which the teaching community can go to the campuses with prestige, honour and dignity which they deserve and the nation will ever expect that the dignity, honour and prestige is restored to the teaching community. Finally, I would again appeal to you: Please listen to the voice of reason and argument and do not make it an issue of prestige which will not be in your interest or in the interest of the Government or the interest of the country or in the interest of the student community or in the interest of the teaching community. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Yes, Mr. Minister.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Mr. Vice-Chairman, Sir, eighteen honourable Members have participated in this debate and I am very happy that the implications of all that is involved in this strike have come out by and large.

In the first place, I should express my deep sense of gratitude to all the honourable Members who have expressed certain expectations from me personally. I feel very grateful to them because I have done education all my life and I hope to do education during the rest of my life, wherever I am, whatever I will be looking after, not looking after, and it is a passion with me and it will continue. If it had been a question of money, a question of monetary benefits, again, maybe it would not have been an insurmountable problem. We can strike a compromise somewhere between what they demand and what we can give. But, Sir, I would like to say, in all sincerity, that it has become a little difficult to solve the fact that there are certain postulates of the New Education Policy in respect of which somehow I feel that I have taken great pains at the instance of the Prime Minister to evolve it with the co-operation of both the Houses of Parliament and the National Development Council. I feel very sincerely that this New Education Policy and certain very essential features, on which there have been very elaborate discussions in both the Houses and in the country right down to the grass-root levels, some of those very very prominent features, should not be done away with or diluted even in the first year of the implementation of the Policy. It would have been very easy for me if I had compromised on those things and it would have been extremely easy for me to get some kind of kudos. But what happened to the Kothari Commission Report? How was it not given a trial in spite of the fact that it is one of the most excellent Reports anywhere in the world? I can vouch for it. Why was it not properly implemented? Why could it not be properly implemented? What happened to many of the other reports which we have had from Commissions of educationists, great educationists, one after another in this country, on matters of education? This has been troubling me, this question has been troubling me? I feel that if the New Education Policy has to be implemented to the hilt, we must be totally and completely faithful to that Policy and loyal to that Policy, both in letter and spirit. I know that this is not an easy decision. I have come to this decision not lightheartedly, not because the other easy way was not available to me. I have come to this decision after due deliberation. It is an unpopular decision to many of those who are concerned. I know that. Today they feel it a little difficult to swallow it. But I am sure that after 10 or 15 years, the coming generations of teachers and students will bless me. What I am really looking for is a situation where the new educational policy, in all its essentials, is implemented to the full. Now, if that is the postulate, there could be variations. I have said in the other House that there are certain essentials. Given those essentials, we could always discuss. But when the essentials themselves are being attacked, when it is said that these essential features are not essential and, therefore, we should do away with these essentials-that is how I under-

stand the situation—then it becomes very difficult for anyone to accept that position. The hon. Members have said and assured me time and again that this is not so, and that the teachers themselves accept the essentials of the new education policy. They accept it not only in words, but in implementational aspects also. But I have not found from what they have written to me so far any evidence of this. Even so, I am prepared to go in the assurances given by the hon. Members. I have no difficulty in talking to the hon. Members and requesting them to come to brass tacks. We can go into the brass tacks. But one thing is very clear to me. It is that the Mehrotra report has been prepared and produced by a galaxy of educationists in this country. May be there are some who do not agree. But the point is that I cannot improve on the calibre of the Mehrotra Committee. I cannot think of persons who are more distinguished. There may be more. But you cannot say that these persons are of an inferior calibre and, therefore, the report produced by them is not be in the best interests of the teachers and of higher education. The tirade has been against that Committee and its report. I will not go into the tirade aspect of it. But I would certainly like to say that we have accepted the report to the extent it was possible. The report says something about the merit promotion scheme. It has been implemented in different ways in different States and in different universities. Some have got very good opinion about it. Others, including the Mehrotra Committee, have expressed an opinion which I need not repeat since Advani Ji himself has read the opinion. I would say that beyond the evaluaton or selection procedures adumbrated in the merit promotion scheme, the new education policy goes one step further. The policy says that evaluation will be continuous and not just at the time of selection. If it is that stringent, if the selection itself is that stringent, then that is precisely what I am saying. If a Lecturer, before being promoted as a Reader, is subjected to the most stringent scrutiny and examination under the merit Promotion Scheme, in effect he is actually attending the Selection Committee. That is why I am making the Reader a selection post. What is the difference? I do not see any difference if that is so. If that is not so, then he has certain built-in inconveniences which are being sought to be removed. So, we cannot have it both ways. I am prepared to talk, I am prepared to discuss with hon. Members who have expressed this opinion. But the opinion expressed by the Mehrotra Committee is something which I cannot wish away. Therefore, since we had made a commitment under certain circumstances that the merit promotion scheme would continue, we have continued it we have not scrapped it. But in the new package, we have given something which is different from the merit promotion scheme. If it is considered that the new package is even lenient academically than merit promtion scheme, then it should be easy for them to swith over to the new scheme. The package is different the content is different. And if someone who really wants to do his career as a teacher according to the new package and ge the higher benefits of the new package, it should be possible for him to do so. It should be available to him. This is the basis on which the new scheme has been prepared, the new package has been put together. Therefore, Sir, there is no question of taking away from the teachers what was given to them. The only thing is that the new package is different. the new benefits are different. And, therefore, let them opt for the new benefits and the new package. If they find that the old package was better, the merit promotion scheme was better individually, they can certainly opt for it.

SHRI LAL K. ADVANI: That kind of duality may be legally dubious. Even from the legal angle it is dubious. The fundamental right of the polity is breached thereby.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I don't think so. In the case of the States' re-organisation we have seen several kinds of service conditions running parallel for a particular period. This has been allowed and I don't think there is any legal difficulty in that. If there is any legal

[Shri P. V. Narasimha Rao]

difficulty, we can always go into that. The point....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, on a point of clarification. Will he agree to talk with the striking teachers, their organisation?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I am coming to that point in the last. Let me at least explain the position and set the record straight because lots of things have been said, and it becomes my duty to set the record straight.

Now, Sir, to start with, it is not correct to say that no consultations were held. We have not only held consultations with the teachers but we have also accepted many of their suggestions. And on the basis of that acceptance, we have changed the package and the new scheme. While finalising the decision of the Government on the Report of the Mehrotra Committee, the opinions expressed by teachers' organisations were kept in view. The Government and the UGC had extensive consultations with the representatives of the All-India Federation of University and College Teachers organisations spread over three days from June 10 to 12, 1987, before the scheme was finalised. The specific matters on which teachers view were accepted and appropriate modifications made in the final scheme are: (1) In respect of the existing incumbents, apropriate relaxations and exemptions have been provided in their placement in the senior scale in selection grades. These relaxations cover M.Phil., Ph.D. qualifications, participations in training and performance apprisal. The teachers had said that since we have not made any arrangement nor is it possible for all of them to appear at these training camps, etc., it should not be made applicable at once, over-night. This was accepted and we have made it so easy for them that they should have no complaint. (2) Although the Mehrotra Committee had recommended a national qualifying examination for recruitment of lecturers, the final decision was not in favour of a centralised examination. To that extent we have departed from the recommendation of the Mehrotra Committee. It is our intention that that test should be conducted at the State level which, I think, is quite reasonable. (3) The pay-scales of Tutors and Demonstrators have been revised. (4) It was clarified that the grades of Professor and Reader would be introduced in suitable and deserving colleges. It was not the intention to restrict that to autonomous colleges, which was how he teachers' associations understood it. That has been clarified abundantly and there is no question of restricting the creation of these posts only to autonomous colleges, some autonomous colleges may have, but some non-autonomous are also likely to have these posts according to the qualifications laid down by the UGC.

In respect of the evaluation procedures and code of conduct, it was decided that the UGC should frame the details in consultation with the teachers. Now, when it comes to evaluation, we have not taken it upon ourselves. The Government has nothing to do in the evaluation processes. Everything is done by the UGC and so far as assessment etc. is concerned, we have left it to the teachers' associations themselves to come forward and give us what they thing should be done by way of assessment, how it should be properly organised and how it should have a linkage with advancement.

Now, Sir, this being the cases the response which we got later was really such that it left no scope for any discussion because they were frontally opposed to everything. At that time, however on the 1st of July, we received a reply, a letter, from the General Secretary of that association which said as follows: Our federation is thankful to the Government of India for holding a detailed discussion with the representatives of our federation prior to the finalisation of the announcement and the announcement of the revised scales of pay for university and college teachers and then without any further delay accepting and forwarding it to the State Governments.

Now, in the face of this how can anyone convince me that we have been unresponsive, we have not talked to them. we have not heard them. What else have we been doing? We have been talking to everyone who is concerned in this and

here is a letter from them. Yes, they know and we also know that we have not been able to accept everything that they said. Nor did they expect a thing like that, that whatever they said we were going to accept but when it is said that no consultations were held, I beg to differ and I would like very clearly to submit to Hon. Members that that charge should not be laid at my door. .

About the pay scales, Sir, the actual scales and the money part of it, I would not go into it because common consent that is not the bone of contention. So, while there is a lot to say about the benefits accruing from the new pay scale, I would not take the time of the House by going into them.

Now, I come to the multiplicity of grades. It has been contended by them that while the Fourth Pay Commission had reduced the number of grades and the scheme approved by the Central Government, here the number of grades has been increased from three to seven. It should first be clarified that under the earlier scheme, there were two grades of lecturers in colleges namely, lecturers and lecturer in selection grade. And there were four grades in universities, namely, lecturer, reader, professor and professor of eminence. Since we have decided not to count the professor of eminence, it means only three, okay, thus making five grades in all. It has been argued that there are at present only three grades as the selection grade of lecturer is equal to that of reader and the grade of professor of eminence is non-operational.

In the revised scheme also there is a selection grade for lecturer which is equal to that of the reader and the professor of eminence, we are keeping apart. Therefore, if these two grades have to be excluded from the existing structure, they should also be excluded from the revised structure. In that case the existing three grades become five grades and not seven. One grade has been increased at the reader's level and one has been increased at the lecturers' level. This is the addition made in the new grades.

Under the Fourth Pay Commission the employees have been given, by and large, stepped up replacement scales. There would, perhaps, have been no difficulty in continuing the earlier system and providing to lecturers replacement scale of Rs. 2300—4000 in place of Rs. 700—1600, and a senior scale of Rs. 3000-5000 against Rs. 1200—1900—There were the old scales and replacement scales were just, what I have read out. What we did, and what is being assailed, is that we decided to add a scale in order to take the Lecturer up to the revised scale of Reader, that is Rs. 3700—5300, which is the replacement scale for Rs. 1500—2250, while was not the Lecturer's grade. Moreover, under the new scheme every Lecturer will get step-up in his or her pay at two stages, in the 9th year and 21st year. In addition, unlike under the merit promotion scheme, which has one-third ceiling on promotion, the senior scale, or selection grade will be available to every Lecturer who qualifies for promotion, without any restriction on the number of posts. I have also assured the other House, and I am giving a similar assurance here. We can provide the numbers, how many posts have to be created. This we did on the doctors' side also the other day. Now this is being lost sight of. Whereas it was confined to one-third, we can go—I don't know—up to two-thirds, or 50 per cent or 60 per cent. We can go up to whatever percentage is needed under the circumstances. We will work it out; UGC will work it out. I do not see any difficulty, and that is the implication of the new scheme. Teachers get a better deal under the scheme offered by the Government. Since it is obvious that pay of teachers would be better as offered by the Central Government, the question arises, why is it being assailed? Why is this scheme being opposed? This is the crux of the matter, and this is where I would like to appeal to the Members that the new education policy is not just mine. It is the joint effort, the joint product of the wisdom of this House. There should be no dilution on that. Now, the new education policy very clearly states this:

> "A system of teacher evaluation, open, participative and data-based will be created and reasonable opportunities of pro-

[Shri P. V. Narasimha Rao]

motion to higher grades provided. Norms of accountability will be laid down with incentive for good performance...."

And it does not stop there.

"....and disincentive for non-performance."

These are the parameters subject to which the new education policy enjoins on me, enjoins on Parliament, on everybody in education teachers, students; managers, Universities, everybody alike, to conform to these parameters. If these parameters are conformed to, then it is a class violation. You have to link advancement and assessment; non-performance should be linked to disincentive, and good performance should result in incentive. These two are inextricably inter-linked in the policy itself, and if anyone can show—I have given this undertaking—me that this linkage can be done in a better manner, than what we have envisaged, I am prepared to consider it. I am prepared to discuss with him and discuss with those who want it. We can certainly go into the merits. According to us and the Government and the UGC, this is the way it could be done. If someone could say there is a better way, I have already given an undertaking that I am not standing on prestige at all; I need not be told that I should not stand on prestige. There is no prestige involved here. It is the principle and the policy which are involved here the new education policy is involved here. Please show me another way. We will make a comparison of both ways. That will naturally take time. And there is no need for going on strike and continuing the strike in an exercise like this. It is going to be an elaborate exercise. I have already said that.

Another point which has been raised is that even if the system of evaluation is satisfactory, some management may implement it in a capricious or an arbitrary manner. Now, in this connection, I would like to draw the attention of the hon.
7.00 P.M. Members to the provision in the new scheme for redressal of grievances to meet such a situation. The same policy says in the chapter on teachers—I think this is one of the most comprehensive chapters that one could imagine about teachers—something definite about incentives, something definite about disincentives and something equally definite about the grievances redressal machinery. It has said that it will be at three levels. There will be a grievances redressal machinery at the institutional level, at the State level and at the Central level. Three levels have been indicated in the policy. And what is it for except to see that capricious implementation is not allowed to go scot-free? This is the reason. Among other reasons this is the reason. There will be so many daily grievances of teachers. They will be looked into by this machinery. Particularly, in the implementation of the policy, this machinery which is the creature of the policy will have to look into these matters even more specially and with greater care.

Now, Sir, about the conditionalities which have been mentioned. There has been some objection. I am really surprised. The Mehrotra Committee has done away with some conditionalities. In fact, for every lecturer, we had the conditionality of an M.Phil. or a Ph.D. Now, we say 'you get an M.Phil or Ph.D. qualification within eight years.' 'Earlier' the condition was, 'you get it first and become a lecturer.' That has change. I fail to see how it has become more unacceptable. We know that in the over-anxiety to become lecturers, what kind of theses were being presented. We have discussed this. In this very House, we have discussed the standard of our Ph.D. theses, the dissentations I am not talking of all dissentations—the general standard of dissentation, because he wants to become a lecturer somehow. We say now that there is no need for such sub-standard attempts; within eight years you complete your dissentations. If you are good you will be promoted.' I do not see what is wrong with this. And when we talk of a professor or a reader, I would respectfully submit to Adavanji and others that we have a particular image in view of a professor and a reader. Let us not sully that view. Let us not allow that view to be sullied althongh, on the monetary

side, we do not want to affect the person adversely on his pocket....

पेट पर न मारिए

This is the old saying in our language:

पेट पर न मारिए पीठ पर मारिए

Have disincentives, but no disincentives of a monetary nature. If you feel that a person is not fit to be called a lecturer, do not call him a lecturer but still pay him the lecturer's salary. If you feel that a person is not fit to be called a professor, do not call him a professor, but still pay him the emoluments of a professor if he has served long enough. If you start calling a person who does not deserve to be a professor by the appellation of professor, what would a deserving professor think? Why should he really labour? Why should he make an effort to be called a really good professor? Why should he do anything to be called a professor at all? If everybody is to be called a professor, whether he deserves it or not, it is not a correct view. On the monetary side, let us not harm him. But on the side of academic distinction which a professorship denotes, let us not dilute it. This is the basis of this scheme in regard to professors and readers which has been made on selection basis.

Now, Sir, about some percentages, some figures, I have given. Advaniji has raised an objection. Naturally he got it from those who raised the objection. I would like to tell him 'Yes'. When I gave the figures. I was having the universities in view.

Taking the colleges, however, it so happens that according to our information by January 1985, out of a total 3139 permanent teachers in Delhi colleges, as many as 1574, i.e. 50 per cent has been promoted to the selection grade which is the Reader's grade. We are not calling them Readers because Reader's grade is not available in the colleges, but it is called the Selection Grade Lecturer which is equal to a Reader. So it is not that the pyramid is any better—of course Advani Ji perhaps anticipated this and he made a statement to say that he does not agree with the pyramid idea at all. If he does not agree with the pyramid idea and if it is conceded that everybody could a Professor and nobody need be a Lecturer, then that is a different argument tealtogether. That is for academicians and others to consider. But if there has to be a pyramid, if the number of Profesors by definition has to be less than the number of Readers and the number of Readers has to be less than the number of Lecturers, as normal human being expect, as mortals expect then that is not obtaining in the Delhi University today. That is what I wanted to say. For various historical reasons, maybe we agree or we do not agree, but this is what I wanted to clarify. I have called for the 1987—the latest figures—also and if anything, it is going to be a little more on the distorted side.

Sir, I can go on and on because there is a lot to be said, but in the spirit in which this debate has been conducted in this House, I would not like to go into many details. I say that there are certain parameters emanating from the new education policy. Those have been the main concern. There is nothing to say about bureaucracy, autocracy and democracy. At least let the hon. Members not be as uncharitable to me as to say that I have been influenced by someone. I have drudged day and night for this policy. According to my understanding of the policy, I think that what we have offered is the right thing to do. If the hon. Members, educationists say that there is another way, I am prepared to discuss it. But for that there need not be a strike. The continuation of the strike is totally unhelpful in that process because we have to come together, we have to say certain harsh words to each other, we have to fight with each other, argue with each other and then come to a conclusion, which needs a different atmosphere altogether. So while saying that I am prepared for a dialogue like this, I would like the teachers to create an atmosphere by going back to work. It may take one month or two months I really do no know. But if the hon. Members have any confidence in me that I mean business, they should advise the strikers, the teachers, to go back to work.

SHRI LAL K. ADVANI: This is saying "No" to a unanimous demand made by this

[Shri Lal K. Advani]

House today. The unanimous demand is that you should speak to the teachers and their representatives. You have said "No" to that demand which is wrong.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: In fact I have already said that there is no communication gap between the teachers and me. It is quite clear to me. I want to be convinced that the basic postulates are common. Once that is done, we can certainly....

SHRI LAL K. ADVANI: After all Education Policy is not such a sacrosanct document and gospel truth. After all the implementaion has to be by the teachers. And if you are not going to speak to the teachers..

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: If we do not agree on the postulates of policy, what are they going to implement?

SHRI LAL K. ADVANI:: I do not think grades are an integral part of the policy. (*Interruptions*) I am very sorry that the unanimous demand made by the House has been rejected by the Minister.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I have not rejected it, Sir.

SHRI CHITTA BASU: When he is willing to have dialogues with us, what is worng in his having a direct dialogue with the teachers? ..(*Interruptions*).. Mr. Vice Chairman, my point is, he has conceded that he is prepared to talk with us as Members of this House. What have the Members of this House got to do? If he is willing to talk with us what is his objection for not talking directly with the teachers?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, on a point of clarification. It has been the unanimous suggestion to the Minister that he should talk with the striking teachers. By turning down such a reasonable thing...

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: There has been no unanimous suggestion or any such thing. You are simply going off at a tangent. Everyone has expressed his views. I have responded. I thing it is not fair to say that there is anything. that has come.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the Minister has turned down the near-unanimous suggestion of the House.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: No, Sir. I have made a careful, meticulous, note of what all has been said here. I have not rejected anything....(*Interruptions*).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at twelve minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 19th August 1987.